श्री रबी राय]

सवाल है। कमेटी साइट-सीइंग कर रही है, एक राज्य सरकार का ऐतराज था कि हमारे राज्य में आए . . .

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Ladies are all over India. How does he expect that the lady should not visit all places of India?

**श्री रबी राय** : श्री ओम् मेहता मजाक न करें, सीरियसली देखें कि यह क्वेश्चनायर ग्रामीण इलाकों तक जाएगा। महिलाओं से पूछताछ करने का काम, यह भी नहीं किया। बी० डी० ओज और ग्राम सेविकाओं से ये जवाब ले रहे हैं। इस बारे में श्री ओम् मेहता साहब नुरुल हसन साहब से बातचीत करें और इस सारी की सारी कमेटी की क्या दिक्कतें थीं और किस तरह से . . .

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Who are the members?

**श्री रबी राय** : मुझे पता नहीं। यह तो एजुकेशन मिनिस्ट्री के मातहत बनाई गई है। इसलिए मैं कहूंगा आप ओम् मेहता जी को डाइरेक्शन देंगे कि इसके बारे में सात दिन के अंदर क्या स्थिति है उसको बताएं। यह तो जो अखबार में खबर निकली है वह मैंने बताया, हो सकता है जो अखबार में निकला उससे ज्यादा बेईमानी चली होगी; इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बारे में ओम मेहता साहब हमको कुछ वचन दें कि इस बारे में सारी स्थिति यह सत्र खत्म होने के पहले हमें बतायेंगे। अरे भाई ओम् मेहता साहब, जरा खड़े होकर कुछ कहिए तो।

**श्री ओम मेहता** : मैं मिनिस्टर साहब को कह दूंगा।

**श्री उपसभापति** : ओम् मेहता सब सुनते हैं और सुनाते हैं।

SHRI BHUPESH GUPTA : Sir, I suggest, you should find out or you become an honorary member of that Committee.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now we pass on to the discussion on the Report of ihe Commissioner for Scheduled Castes Jind Scheduled Tribes.

*[At tMs stage the Minister of State in tin-Ministry of Railways, Shri Mohd. Shaft Qureshi, entered the House]*

SHRI BHUPESH GUPTA : The Railway Minister has just now come. Like the railway trains you too are late. Tradition you have maintained; I do not blame you. When the railway matter was raised here, you should have been in this House. Tomorrow there will be a *dharna* led by S.A. Dange before Parliament.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : It was not on the time-table. So, how can he be late?

SHRI BHUPESH GUPTA : It is understood.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Yes, Mr. D. K. Patel.

## MOTION RE. TWENTY-FIRST REPORT OF THE COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRD3ES FOR THE YEARS 1971-72 AND 1972-73—contd.

**श्री डी० के० पटेल** (गुजरात) : उपसभापति महोदय, हमारे सामने 1971-72 और 1972-73 के वर्षों की अनुसूचित जातियों एवम् अनुसूचित जन जातियों के आयुक्त की 21वीं रिपोर्ट विचारार्थ प्रस्तुत है। मैं अपने वक्तव्य में आदिमजातियों *की समस्याओं के बारे में कुछ प्रकाश डालना* चाहता हूं। वैसे इन जातियों की सबसे बड़ी समस्याएं इन 25-27 सालों से जो हैं वे समस्याएं मुख्य रूप से दो हैं—एक तो शैक्षिक समस्या है और दूसरी आर्थिक समस्या। शिक्षा के क्षेत्र में, खास तौर पर जहां ये आदिम जातियां बसती हैं वहां पर महात्मा गांधी के 'नयी तालीम' के सिद्धांत के ऊपर आधारित कुछ बुनियादी तालीम देने की संस्थाएं चलाती हैं। गुजरात में उनका बहुत बड़ा प्रचलन है वे एक कम्पैक्ट एरिया में है जहां आदिम जातियों की बहुत बड़े पैमाने पर बस्ती है। उसी तरह से महाराष्ट्र में भी श्रमिक विद्यालय के नाम से महात्मा गांधी की नयी तालीम में शिक्षा दी जाती है।

वैसे महात्मा गांधी जी की नई तालीम की जो शिक्षा पद्धति है, कोई बुरी नहीं है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा सिद्धान्त है, शिक्षा का । जैसा कि उसमें स्वावलम्बन का सिद्धान्त है, चरित्र निर्माण का सिद्धान्त है और समाज में उपयोगी शिक्षा की बात उसमें है । लेकिन जो बुनियादी संस्थाएं चलती हैं, उनमें इन सिद्धान्तों का कोई प्रचलन नहीं होता है और व्यवहार में इन सिद्धान्तों का कोई असर नहीं होता है । महात्मा गान्धी के नाम पर जो संस्थाएं चलती हैं, वे एक प्रकार से पोलिटिकल सेन्टर्स बनी हुई हैं और सरकार का पैसा उनमें लगाया जाता है । इन संस्थाओं में जो विषय पढ़ाये जाते हैं, वे ऐसे विषय हैं जो कि ज्यादातर इन संस्थाओं में सिखलाये जाते हैं और ये विषय हैं काश्तकारी के सम्बन्ध में, तुनाई और बुनाई के सम्बन्ध में और इन चीजों के बारे में प्राथमिक ज्ञान दिया जाता है और इन विषयों से कोई स्वावलंबन का सिद्धान्त चरितार्थ नहीं हो सकता है । ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां से आदिम जातियों के बच्चे पढ़कर निकलते हैं जहां पर उन्हें थोड़ी प्राथमिक वस्त्र-विद्या आदि का ज्ञान ही दिया जाता है । इस तरह से वहां पर काश्तकारी, तुनाई और बुनाई के बारे में प्राथमिक ज्ञान दे दिया जाता है । लेकिन वहां पर कोई टैक्नीकल ज्ञान बढ़ईगिरी का, लोहारगिरी का या फिर इसी तरह से कोई टैक्नीकल ज्ञान नहीं दिया जाता है और इसका परिणाम यह हुआ कि इन 27 सालों की पढ़ाई के बाद भी जो बच्चे पढ़कर निकले हैं, वे सब बेकार हैं । इस तरह के बच्चे न तो गांव में ही काम कर सकते हैं और न ही शहरों में ही काम कर सकते हैं और ये सब चरवाहों की तरफ गांवों में घूम रहे हैं । होना यह चाहिए था कि इन बच्चों को कारपेन्टरी, मोटर मैकेनिक, टर्नर और प्राइमरी इंजीनियरिंग की शिक्षा दी जाती जो कि इन्हें नहीं दी गई । ये बच्चे जो गांवों में किसान और मजदूर के बच्चे हैं, उनकी आज बड़ी बुरी अवस्था है । इसका मतलब यह है कि इन बच्चों की शिक्षा के लिए जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह सब बेकार हो रहा है और इस तरह से इन बच्चों का भी भविष्य खत्म हो गया है । दुःख इस बात का है कि इस बारे में बहुत बार यहां पर सुना गया है और शिक्षा मंत्री द्वारा यह कहा जाता है कि इस बारे में समितियां विचार कर रही हैं, लेकिन शिक्षा पद्धति में नया मोड़ और नया सुधार लाने के बारे में कोई चिन्ता नहीं करता है । इस तरह से हम पिछड़ी हुई जातियों के बच्चों को और आदिमजाति के बच्चों को आगे नहीं ला सकते हैं ।

शिक्षा की जब बात होती है तो उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि पोस्ट ग्रैजुएट क्लासों के लिए आदिम जातियों के लिए कुछ आरक्षित स्थान होने चाहियें । हमारी यूनीवर्सिटीज की सैनेट इस सम्बन्ध में गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं करती हैं और इसका परिणाम यह होता है कि इन लड़कों को वहां पर प्रवेश मिलने में दिक्कत होती है । आजकल यह चीज हो रही है और इसलिए मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह यूनीवर्सिटी सैनेटों को निर्देश दे कि इन लोगों के लिए आरक्षित स्थान रखे जायें ताकि उन्हें प्रवेश पाने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो ।

ऐसे भी महाविद्यालय हैं, जहां पर आदिम जाति के बच्चे पढ़ते हैं, जहां सरकार की ओर से उन्हें स्कालरशिप मिलता है, वहां पर जो ऐडहौक पेमेंट किया जाता है, वह केवल सितम्बर और अक्तूबर में ही किया जाता है जब कि कालेजों के सत्रों का प्रारम्भ जून और जुलाई के महीने में ही हो जाता है । मेरा कहना यह है कि अगर उन्हें ऐडहाक पेमेंट स्कालरशिप के सम्बन्ध में कालेज खुलते समय मिल जाय तो उन्हें पुस्तक खरीदने के लिए और दूसरी व्यवस्था करने के लिए सुविधा हो जायेगी । इस तरह की जो व्यवस्था है वह सरकार आज तक नहीं कर सकी है ।

परिणाम यह होता है कि आधी पढ़ाई हो जाती है और बच्चों के पास पुस्तकें नहीं होती । यह भी देखने में आया है कि कालेज में जो सत्ताधारी होते हैं उनके पास सरकार की ओर से सेप्टेम्बर, अक्टूबर में पैसे आ जाते हैं लेकिन वे

[श्री डी० के० पटेल]

पेमेंट नहीं करते । उन पैसों को बैंक में रखते हैं और उनसे ब्याज कमाते है। देरी से पैसे देते हैं, कभी कभी तो फरवरी, मार्च तक आ जाता है। यह तो एक मजाक है । अगर स्कालरशिप का सही उद्देश्य पूरा नहीं होता तो ऐसे स्कालरशिप से क्या फायदा ? अगर आर्थिक चिन्ताओं में विद्यार्थी रहेगा तो उसका पढ़ने पर भी असर होगा। इसलिए यह चाहिए कि जून-जुलाई के प्रारम्भ में ही कुछ एडहाक पैमेंट उनको मिलना चाहिए।

दूसरी समस्या आर्थिक समस्या है । जमाने से उनका आर्थिक बेस नहीं है । जंगलों में जो कृषि योग्य जमीनें पड़ी हुई हैं वे जंगल में रहने वाले आदिम जाति के लोगों को मुफ्त में दे देनी चाहिए। बहुत सी स्टेट्स में ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट फलो लैन्ड्स हैं जंगल के विस्तार के अलावा भी । उनमें से भी कुछ जमीनें उनको मिलनी चाहिए ताकि इन भूमिहीन खेत-मजदूरों को खेती का पेशा करने का मौका मिले और आर्थिक समस्याओं में परिवर्तन आ सके।

जंगल में काम करने वाले इन मजदूरों को कोई ट्रेनिंग नहीं दी जा रही । वहां इन लोगों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं उनमें काम करने वाले लोग, ऑफिस बियरर्स उनके काम से परिचित नहीं हैं, सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जिन्होंने कामदारों के पैसों से मोटर कारें खरीदी हुई हैं । ऐसे आफिस बियरर्स की क्या जरूरत है ? आदिम जाति के लोगों को ही ट्रेनिंग देकर अगर व्यवस्थित रूप से सोसाइटी चलाने के लिए तालीम दी जाय तो उसका कुछ फायदा हो सकता है । जंगल कामदार सोसाइटीज खासकर पोलिटिकल वर्कर्स के हाथ में हैं । जो मुनाफा होता है उसे वे सरकार को कम दिखाते हैं । कुछ बोनस दे देते हैं, बाकी का रुपया इलैक्शन फंड में घसीटते हैं, मोटर में घूमते हैं, प्रचार करते हैं । इस तरह वे इन मजदूरों के पसीने की जो कमाई है उसे इलैक्शन में लगाते हैं जो कि बहुत बुरा है ।

जंगल में बसने वाले लोगों का प्राथमिक उद्योग बांस उद्योग है । सरकार ने ऐसी नीति अपनाई है जिसकी वजह से उनको बांस नहीं मिल रहा। कभी कभी फारेस्ट डिपार्टमेन्ट बांस कटवाता है लेकिन तीन महीने के बाद जाहिर करता है कि बांस अब तैयार है, उठाइए । तीन महीने के बाद वह बांस उद्योग के काम में नहीं आ सकता । ऐसी छोटी छोटी बातों में हम इन गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं । वैसे 71-72 और 72-73 के प्रतिवेदन में भी पृष्ठ 183 पर इस बात का जिक्र है कि जंगल में बसने वाली आदिम जातियों को सरकार के फारेस्ट डिपार्टमेंट ने परेशान कर रखा है । उनकी छोटी छोटी सुविधाएं, जो एक जमाने में उन्हें अधिकार के रूप में प्राप्त थीं, अब ले ली गई है।

आयुक्त ने कमेंट किया है--

इन लोगों के पास और कोई जीवन निर्वाह का साधन नहीं है । इनके पास बांस या पत्ते तोड़ने के अलावा कोई साधन या कोई और धंधा नहीं हैं । अगर इनको बांस मुक्त रूप से नहीं मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि हम लोग इनको रोजी और रोटी भी नहीं दे सकते । इन प्राथमिक सवालों पर बार बार फारेस्ट डिपार्टमेंट उनको परेशान करता है तो इसका मतलब यह है कि हमारे सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने वाले अधिकारी उन लोगों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण नहीं रखते हैं ।

"The Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission has commented that the tribal who formerly regarded himself as the lord of the forest was, through a deliberate process, turned into a subject, and placed under the forest department. The tribal villagers were no longer essential part of the forests, but were merely on sufferance. The traditional rights of the tribals were no longer recognised as rights."

एक और बात आपसे कहनी है । आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन के प्रारम्भ में ही यह कह दिया है कि देश के विकास के मुख्य प्रवाह से वे जातियां अछूती हो गई हैं । देश ने जो उपलब्धियां कीं उनसे जो प्राप्ति हुई उनसे भी वे वंचित रह गये। लाभान्वित नहीं हुई । इसका कारण क्या है? आयुक्त ने इसका कारण बताते हुए अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमारी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है। हम चाहते हैं कि यह करना चाहिए, यह करना चाहिए लेकिन उसका कार्यान्वयन होता नहीं । इसके लिए एक तो हमारे डिपार्टमेंट्स जिम्मेदार हैं । साथ ही साथ उन पर निगरानी करने वाले जो भी सरकार के टाप लेवल के आदमी हैं उनकी उनके प्रति कोई खास दृष्टि नहीं, कोई ध्यान नहीं है । हम देखते हैं कि उनको कोई खास लाभ नहीं हो रहा है ।

कुछ आरक्षित स्थान हर एक कैटेगरीज में रखे हुए हैं । लेकिन वे भरे नहीं जाते । क्या इतने लोग पढ़े लिखे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों में नहीं हैं? हर एक गांव में आपको ग्रेजुएट्स मिलेंगे, डबल ग्रेजुएट्स मिलेंगे लेकिन वे बेकार पड़े हुए हैं । एक नियम बना रखा है सूटेबिलिटी का । उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, फिर सूटेबिलिटी के नियम के आधार पर उनको बाहर निकाला जाता है ।

"You are not fit, you are not suitable, for ihis post"

यह नहीं होना चाहिए । वैसे 1970-71 की रिपोर्ट में आयुक्त महोदय ने भी पृष्ठ 51 पर इस बात का जिक्र किया है कि यह सूटेबिलिटी या ऐसे कुछ कारणों से येनकेन प्रकारेण हटाने की जो प्रवृत्ति है इसको रोकने के लिए कुछ करना चाहिए । आज भी एक ऐसी स्थिति है कि जहां भी जितने भी आरक्षित स्थान हैं वे अभी तक भरे नहीं हैं । इसलिए उन्होंने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया है "किसी भी राज्य और संघीय प्रदेशों की राजकीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के प्रतिशत में वृद्धि करनी चाहिए । अगर जरूरत हो तो उनके प्रतिनिधित्व के निर्धारित कोटे को कम से कम समय में पूरा करने के लिए वे विशेष भरती अभियान भी शुरू करें।" मतलब यह है कि पहले के आयुक्त ने और अभी के आयुक्त ने भी इस बात को बड़ी गम्भीरता से स्पष्ट किया है कि आरक्षित स्थान जो हैं उनको भरने के लिए सरकार को जल्दी से ठोस कदम उठाने चाहिएं। वैसे कुछ उदाहरण आपको पेश करता हूं।

1 P.M.

गुजरात राज्य में प्रथम वर्ग की सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत आरक्षित स्थान हैं लेकिन अब तक जो फर्स्ट क्लास की सरकारी सेवाएं हैं उन में 0.63 यानी एक प्रतिशत से भी कम जगहों पर आदिम जाति के उम्मीदवार सरकारी नौकरी प्राप्त कर सके हैं । इसका मतलब यह हुआ कि 27 सालों में भी जो 10 प्रतिशत रिज़र्वेशन है उसकी 0.63 परसेन्ट जगहों पर इन लोगों को नियुक्त किया गया। इसी तरह से गुजरात में आदिवासी विकास खंड के नाम पर जो ब्लाक्स हैं वे 57 के करीब हैं लेकिन इन विकास खंडों में भी कोई आदिम जाति के लोग काम नहीं कर रहे हैं बल्कि ऐसे आदमी काम कर रहे हैं जिनको इस प्रजा के प्रति, पिछड़ी हुई जनता के प्रति कोई खास सहानुभूति नहीं है । फलस्वरूप जो पैसा उन के लिए दिया जाता है उसका सही उपयोग नहीं होता है और वैसे ही वापस हो जाता है । उनका कहना था कि हम एक साल में इतना रुपया खर्च नहीं कर सकते । हमारे पास रुपया आता है परन्तु 31 मार्च तक खर्च नहीं कर सकते इसलिए हमें भारत सरकार की तिजोरी में वापस भेजना पड़ता है । इसका मतलब यह हुआ कि पैसा जो सरकार आवंटन करती है इन जातियों के कल्याण के लिए, वह पैसा वैसा का वैसा साल भर पड़ा रहता है । अगर इसी तरह से यह सिलसिला चलता रहा तो मैं समझता हूं कि ठीक नहीं होगा। जैसा कि प्रतिवेदन के जनरल रैव्यू में लिखा है इसका एक परिणाम यह आ रहा है कि जो पढ़े-लिखे इन जातियों के लोग हैं उनमें एक प्रकार की कुण्ठा का भाव पैदा हो रहा है और कुछ असंतोष उनमें पैदा हो रहा है । आयुक्त के शब्दों

[श्री डी० के० पटेल]

में अगर देखा जाए तो उसमें यह है कि, "शिक्षित युवा वर्ग में असन्तोष तथा असुरक्षा का बोध उत्पन्न हो गया है।" [70-71 की रिपोर्ट में] उनके दिमागों में असुरक्षा तथा आर्थिक दुर्बलता की भावना गहरी होती जा रही है जिसके कारण अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की भावना भी बलवती हो रही है । अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के करोड़ों लोगों के मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होने के कारण हमारी राष्ट्रीय एकता की जड़ों पर भी प्रहार होता है और यह लोकतंत्र के लिए भी खतरा है । अब समय आ गया है कि राष्ट्र इनके सम्भावित दुष्परिणामों की ओर ध्यान दे तथा इन लोगों के प्रति सद्व्यवहार प्रदर्शित कर इनके विश्वास को जीतने के लिए ईमानदारी पूर्वक हर सम्भव प्रयत्न करें जिससे कि ये लोग यह अनुभव कर सकें कि राष्ट्र की समृद्धि में वे भी अन्य लोगों के समान हाथ बंटा रहे हैं । अब समय आ गया है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के उद्धार के सवाल पर अधिक गहराई से विचार किया जाए और उनको यथा शीघ्र देश के अन्य लोगों के समान समान अवसर देने के उपाय किए जाएं।

अन्त में एक दो बातें ही मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । प्रतिवेदन में कहा गया है कि इन जातियों के उत्थान के लिए जो कदम उठाने हैं वे ढुलमुल नीति से नहीं उठाने चाहिए, उनको दृढ़तापूर्वक उठाना चाहिए । इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर सरकार सही तरीके से पिछड़ी जातियों को आगे बढ़ाना चाहती है तो केवल मात्र पालिसी बनाने से कुछ नहीं होगा और अभी तक स्थिति यह है कि सरकारी अधिकारियों को इस संबंध में जो अधिकार दिये गये हैं उनके माध्यम से वे इस नीति को पूरी तरह से कार्यान्वित नहीं कर पा रहे हैं । कमिश्नर ने भी इस बात की अपेक्षा की है कि इस प्रकार के कुछ अधिकार उनको दिये जायें । ताकि जहां-जहां भी किसी प्रकार का कोई अन्याय हो और इन जातियों को परेशान किया जाता हो तो वे ऐसे मामलों की अच्छी प्रकार से जांच कर सकें और अपराधियों को दंडित कर सकें । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आयुक्त को ऐसी सत्ता देनी चाहिये । सरकारी तंत्र को भी इसके लिए जागरूक रखना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य समाप्त करता हूं।

MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 2 p.M.

The House then adjourned for lunch at six minutes past one of the clock.

The House reassembled after lunch at three minutes past two of the clock. The Vice-Chairman (Shri V. B. Rani), in the Chair.

**श्री देवराव पाटिल** (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजातियों की जो कुल संख्या है वह भारत की जनसंख्या के 1/5 से कुछ अधिक है, यानी भारत की जो जनसंख्या है उसका 22 प्रतिशत उनकी संख्या आती है ; और इस लिए यह रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है । प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी जी को जब कभी मौका मिलता है वे जन-जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के बारे में उनके कल्याण के बारे में हार्दिक सहानुभूति की भावना प्रकट करती रहती हैं । उनका यह निश्चय है कि जनजाति और आदिमजातियों के उद्धार के बिना देश का उद्धार नहीं हो सकता है और इसलिए पिछड़े वर्गों की अब उपेक्षा कोई भी नहीं कर सकता । फिर भी ये जातियां अब भी सामाजिक और आर्थिक अन्याय सहन कर रही हैं और इसी का यह नतीजा है कि देश में आर्थिक और सामाजिक असमानताएं जोरों से बढ़ रही हैं और आदिवासियों और अनुसूचित जातियों का जो पिछड़ापन है उसी में ये असमानताएं और परेशानियों की जड़ ज्यादा मालूम होती है । इसमें कमी करने का केन्द्र सरकार ने और खासु कर के प्रधान मंत्री ने संकल्प किया है । उनके निर्देश को और उनके मानस को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने इस रिपोर्ट में जो महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं, सारे विषय पर उन्होंने जो खयाल दिया है और कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं उसके लिए यह आयुक्त और उनके कर्मचारीगण धन्यवाद के पात्र हैं ।

सभापति महोदय, यह रिपोर्ट 71-72 और 72-73 की है, 73-74 निकल गया और 74-75 मार्च में खत्म होने वाला है । मुझे समझ में नहीं आता कि यह दो-दो साल बाद रिपोर्ट क्यों आती है । मैंने कल भी अपना यह विचार कहा था कि कमीशन की रिपोर्ट जब आती है तो उसके साथ कमीशन की रिकमेंडेशन्स पर इम्प्लीमेंटेशन की पिछले साल की रिपोर्ट भी आ जाये तो दूसरे साल की रिपोर्ट पर बहस करने में सुविधा हो जाती है । इसी-लिए आपने देखा होगा कि लोकसभा में 70-71, 71-72, 72-73 की रिपोर्ट चर्चा के लिए नहीं ली गई और वहां यह मांग रखी गई कि जब तक पिछले साल की इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट नहीं आती तब तक यह बहस उतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी । इसलिए मेरा सुझाव है कि कमीशन की रिपोर्ट के साथ इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट बहस के लिए जरूर होनी चाहिए जिसके आधार पर हम बहस कर सकें । कल ऐसा कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हमने रिकमेंडेशन भेजी है और उनका उत्तर नहीं आया । हम 25 साल से देखते आ रहे है कि सेंटर रिकमेंडेशन भेजता है स्टेट

SHRI N. G. GORAY (Maharashtra) : Sir. where ix the Minister in charge of this subject ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B RAJ (J): Anyhow the Government representative is here.

SHRI N. G. GORAY: But the Minister should be present here. Is it not ?

SHRI N1REN GHOSH (West Bengal): Sir, Mr. A. P ."Sharma is here. Mr. Sharma, are you the Minister in charge of this ?

SHRI A. P. SHARMA : It is not necessary that the Minister must be here. Anybody from the Government would be enough.

श्री कल्प नाथ (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है । विरोधी दल के लोग भी तो नहीं हैं । आपको क्या दिलचस्पी है हिन्दुस्तान के बैकवर्ड लोगों में ।

SHRI N. G. GORAY': But we are not in charge of anything.

श्री देवराव पाटिल : इसीलिए मंत्री महोदय ने यह कहा कि...

SHRI NIREN GHOSH : This, of course, shows tbe way in which the Government treats

श्री देवराव पाटिल : इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट पेश न करने का कारण मंत्री महोदय ने यह कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के पास हमने रिकमेंडेशन्स भेजी हैं लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया । मैं समझ सकता हूं कि जो आज की रिपोर्ट है उसके इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट न आए लेकिन 70-71 की रिपोर्ट में जो रिकमेंडेशन हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट क्यों नहीं पेश होती । अगर 70-71 की रिपोर्ट पर चार-चार साल में इम्प्ली-मेंटेशन की रिपोर्ट नहीं आती तो उसके बारे में मंत्री महोदय को कुछ करना चाहिए । खेद की बात है, जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रधान मंत्री इतने जोर से शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास के बारे में कहती हैं लेकिन उन्हीं का गृह मंत्रालय इस बारे में कोई दिल-चस्पी नहीं लेता है । मैं आपके मारफत यह प्रार्थना करूंगा कि इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट सदन में कम से कम एक साल के बाद अवश्य मिल जानी चाहिए ।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि इन लोगों पर काफी खर्चा किया गया है । कल बतलाया गया था कि चौथी पंचवर्षीय योजना में इन लोगों के विकास के लिए हमने जो खर्च किया है वह 450 करोड़ रुपया है । पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए जो अलग से प्राविजन किया गया है वह 225 करोड़ रुपया है । जो हमारे पास मिनिमम प्रोग्राम विकास का है, उसके लिए हमने काफी रकम रखी है । लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के विकास कार्य के लिए जो मशीनरी हमने तैयार की है, जो केन्द्रीय कार्यालय तैयार किये ह, उनके अलावा आज हमारे पास क्या है ? रिपोर्ट पढ़ने से आपको पता लगेगा कि आयुक्त जो सिफारिश करता है और उनको खुद काम जो करने होते हैं उनके लिए उनके पास राज्यों में कोई मशीनरी नहीं है । हम सब

these poor people. When the so-called debate is going on, the Minister in charge of this subject is absent!

[श्री देवराज पाटिल]

लोग आयुक्त के काम की तारीफ करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि सेंटर में तो आयुक्त का ऑफिस है, लेकिन स्टेटों में आयुक्त का कोई आफिस नहीं है । 1967 तक तो स्टेटों में इस तरह के आफिस थे, लेकिन 1967 के बाद वे बन्द कर दिये गये और आज भी वे बन्द पड़े हुए हैं । इसका नतीजा यह हुआ है कि जो सिफारिशें इन लोगों के संबन्ध में की गई हैं, वे सब कागजों पर ही पड़ी हुई हैं और स्टेटों से जो सुझाव आते हैं या उनको जो सुझाव दिये जाते हैं, वे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं । राज्यों में उनके पास अपना काम करने के लिए कोई मशीनरी नहीं है और स्टेट सरकार के आफिसरों के भरोसे उनको निर्भर रहना पड़ता है । मैं यह बात अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं बल्कि सरकार ने इन लोगों की हालत को सुधारने के लिए जो कमेटी एपाइन्ट की है, जो पार्लियामेंटरी कमेटी बनाई है, उसके टर्म्स आफ रेफरेंस में यह बात आती है कि इन लोगों की हालत सुधारने के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है ? उस कमेटी ने यह सिफारिश की है और जो उसने पहिली रिपोर्ट दी है, उसमें उस ने कहा है कि सरकार ने जो खराब काम किया है वह यह है कि उसने 1967 में इन लोगों के लिए जो आफिस थे उन्हें बन्द कर दिया । मेरे पास इस समय टाइम नहीं है ताकि मैं विस्तार से रिपोर्ट की बात बतला सकूं । अगर मैं रिपोर्ट के बारे में बतलाने लगूं तो मुझे तीन, चार घंटे लग जायेंगे । इस रिपोर्ट में इस कमेटी ने यह कहा है कि इस तरह के जो आफिसेज स्टेटों में थे वे बन्द नहीं किये जाने चाहिए थे और इन आफिसों को फिर से खोला जाना चाहिये । ला-मिनिस्टरी की भी राय यही है । जिस एजूकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से यह कार्य किया जाता था, उस विभाग ने भी यह कहा है कि यह कार्य उससे अलग कर दिया जाए और वह कार्य होम मिनिस्टरी को दिया जाना चाहिये । इस कार्य में जो कमियां है उन्हें दूर किया जाना चाहिये ।

मैं आप के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो सेनापति को एपाइन्ट करते हैं । अगर उसके नीचे आफिस नहीं होगा तो वह अच्छी तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकेगा । इसी तरह से मेरे कहने का मतलब यह है कि जब तक हम इसके लिए आर्गनाइजेशन को मजबूत नहीं करेंगे, इसमें आफिसरों को एपाइन्ट नहीं करेंगे, उनको इस कार्य के लिए जितना धन चाहिये नहीं देंगे, तब तक यह कार्य हमारा कागज पर ही रह जायेगा । आज आजादी के 26 वर्ष के बाद भी जैसी उनकी पहिले हालत थी, वैसी ही हालत आज भी है । यह बहाना किया जाता है कि आर्थिक परिस्थितियां और कठिनाइयां है और हमारी इकौनोमिक कंडीशन्स ऐसी नहीं है कि हम लोगों को इस काम के लिए एपाइन्ट कर सकें । मैं इस बात को समझ सकता हूं कि इकौनामिक कंडीशन आज हमारे देश की खराब है, लेकिन आज यह विभाग ऐसा है जहां इस जाति के लोगों को पेट भरने के लिए और कोई चारा ही नहीं रह गया है । जो इन जातियों के गरीब लोग है, उन लोगों को एपाइन्ट करना ही होगा और उनको एपाइन्ट करने में आर्थिक अड़चनें नहीं आनी चाहिये । मैं आपकी मार्फत इस मुद्दे पर ज्यादा जोर नहीं देता हूं लेकिन कहना चाहता हूं कि जब तक आप इस विभाग को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे तब तक कोई भला अनुसूचित जातियों का नहीं हो सकता है । यहां पर सेंट्रल आफिस आपका है आर०के० पुरम में । उसकी वहां क्या जरूरत थी, वहां हमारे सदस्य नहीं जा सकते हैं, न एम० पी० वहां जा सके, न एम० एल० ए० जा सके, स्टेट मिनिस्टर या मिनिस्टर नहीं जा सकते, अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों के लोग इतनी दूर नहीं जा सकते । ऐसी जगह यह आफिस रखना चाहिए कि जहां पर जाने की सुविधा हो । वहां पर आफिस में है क्या ? वहां पर इतने कर्मचारी भी नहीं हैं । तो मेरे कहने का मतलब यह है कि इस आर्गनाइजेशन को स्ट्रेंथन करना चाहिए ।

दूसरा महत्वपूर्ण सुझाव मेरा यह है कि अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की संख्या भारत में क्या है, इसको जानने का कोई तांत्रिक तरीका नहीं है, आथेंटिक तरीका नहीं है । हर दस साल के बाद हम जब लोगों की जनगणना करते हैं तो उसके बारे में भी एक गोजना होनी चाहिए जिससे हम सही सूचना ले सकें कि हर एक स्टेट में अनुसूचित जातियों और आदिम जातियों की संख्या क्या है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार करके हर दस साल के बाद लोकसभा और राज्य सभा की टेबुल पर आनी चाहिए । लेकिन वह आती नहीं है ।

(*Time bell rings*)

उप-सभाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित आदिम जातियों पर हम बहस कर रहे हैं । लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि कानूनी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या इस समय 22 प्रतिशत है । कुल जनसंख्या का यह पांचवां हिस्सा है । लेकिन जो फैसिलिटीज उनको मिलती हैं वह बहुत कम हैं । आदिम जाति यानी आदिवासी, लोगों की जो परसेंटेज है उसका केवल 4.2 प्रतिशत लोगों को इसका फायदा मिलता है । कुल जनसंख्या के अनुसार केवल 4.2 प्रतिशत लोगों को ही लाभ मिलता है । मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा पाइंट यह है कि इसमें जो लेफ्ट आउट ट्रायबल्स हैं, यानी स्पैसिफाइड तथा अन-स्पैसिफाइड अर्थात् शैड्यूल एरिया या नान-शैड्यूल एरिया का जो रिस्ट्रिक्शन लगा है उससे ये लोग विकास के काम से वंचित हुए है । खास तौर से महाराष्ट्र में विदर्भ में ये लोग हैं और मध्य प्रदेश में ये लोग हैं और कई दूसरी स्टेट्स में भी ये लोग रहते हैं । उनका कोई भी कसूर नहीं है । आपको पता होगा कि संसार में ऐसा अन्याय किसी जमात पर नहीं हुआ है । एक ही फैमिली का एक मैम्बर अगर वह शैड्यूल्ड एरिया में रहता है तो वह शैड्यूल्ड ट्राइब है । उसी का दूसरा भाई अगर नान-शैड्यूल एरिया में रहता है तो वह शैड्यूल्ड ट्राइब नहीं है । उसको अदर क्लासेज में ट्रीट किया जाता है । इसलिए उनको कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं ।

शिक्षा के लिए जो उनके लड़के आते हैं उनकी एप्लीकेशन्स रिजेक्ट कर दी जाती हैं । Your application has been rejected on the ground that your father resides outside the scheduled area.

इसी तरह से शिक्षा में, सेवा में भी वह इस लाभ से वंचित हुए हैं । इसके बारे में कई दफे यहां पर भी और बाहर भी चर्चा हुई है और आनन्द की बात है कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी ने उसमें ख्याल दिया और उन्होंने अनोमली रिमूव करने का आश्वासन दिया ।

इसके बाद उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बिल लोक सभा में पेश हुआ और पेश होने के बाद सिलेक्ट कमेटी बनी । सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स ने सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट भी मानी, सब सदस्यों ने इस बात को माना लेकिन बिल पास न होने से यह रिस्ट्रिक्शन रिमूव नहीं हुआ । इन आदिवासियों की बड़ी संख्या है । इसलिये मैं विदर्भ का एक उदाहरण देता हूं । विदर्भ के 7 लाख आदिवासी ऐसे हैं जिनको फायदा मिलता है और 17 लाख आदिवासी लोग ऐसे हैं जिन को फायदा नहीं मिलता है । मेरा कहना यह है कि क्षेत्रीय बंधन हटाया जाये और जो आदिवासी हैं उन सब आदिवासियों को कानूनी आदिवासी माना जावे ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Shri Rabi Ray—not here; Shri iBanarsi Das—not here: Now. Shri Niren Xihosh.

SHRI NIREN GHOSH: Sir, Gandhiji gave the appellation 'Harijan' to the Scheduled Castes in order to raise their status and said that a Bhangi should become the President of India. Now, unfortunately, some person against whom some adverse reports of the Assembly are there, jis occupying Ihe seat of'the highest office. (Now 'Harijan' has become a cruel joke in India. Let alone the other tribes, during the last one or two years, innumerable horror stories have appeared in tne press as regards the treatment that is meted out to them, and the attitude of the government and the administration or the bureaucracy towards them. There is the case of that village in Punjab where they were not al-jlowed the wells reserved for the honourable castes. Perhaps, there is no caste like the hon. Members of Parliament. I do nor, know whether we are honourable or not. Because they had no other go—there was no drinking water anywhere else—and drew water from them, there were simply killings, massacre, burning, looting and what not. The same story has come from, I should say, Haryana, how the Chief Minister's son was involved and how he was absolved. ' After all, Bansilal and his tribe should be absolved because Bansilal has come in very handy for the Prime Minister and her son in that great, nntoriout Maruti affair...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): This is not covered by the Report.

SHRl NIREN GHOSH: That is why Bansilal's son was absolved. He was implicated in the charge and he was absolved. And that fellow cannot even go to the village. That is how the things have shaped in this Congress raj, the so-called"largest democracy, I should say, the largest undemocratic State in the world. So, that has been their Jot. During the 25 years ot Congress rule, in all spheres, their conditions have deteriorated. All those so-called legislations banning untouchability, reserving percentage of seats for them and so many things are banalities, bourgeois banalities perpetrated on them, perhaps, to throw dust in the eyes of the general public of India. Now, Sir, let me^ touch upon some points as regards the percentage of posts that are reserved for them. I would like the Minister here in the course of his reply to give the percentage of posts reserved for the IAS and IPS and All-India Service categories for Inem and the percentage they have* been able to occupy so far, as regards Class I "and Class II officers, etc. In Committees we have seen—this is my experience—that whenever this point was raised that according to law this percentage should be reset ved for them, pat came the reply : Suitable candidates would not be available. So make it rather ambiguous. That was the reply of the Congress. They were never prepared even for the percentage according to law. In certain Committee meetings I have found it—I need not divulge it here. But, why ? Are they less intelligent ? Does the Congress Government subscribe to the theory that there are different people with different intellects, like under the British, the black-skinned people and the inferior people used to carry white man's burden ? i

DR. V. A. SYED MUHAMMAD (Kerala) : May I seek a clarification from my able colleague ? He is asking for reservation in the IAS and IPS for the Harijans. Now, in Kerala, the Communist Government is opposing any kind of reservation for backward classes. Why ?

SHRI NIREN GHOSH : Which Communist Government ? Achuta Menon Govemment that is now in saddle ? That is not a Ministry in which C.P.M. is a Party.

SHRI N. R. CHOUDHURY (Assam): In Calcutta ?

SHRI NIREN GHOSH : In Calcutta, we were there for a very short period. I am talking of Kerala. *(Interruption).* I am telling you about Calcutta because I know about that, because for a very short period we were in the Governmen!. All the Scheduled Caste people, the down-trodden people, said : We are now human beings. We go before the village higher caste people with heads high. Thousands and thousands have told us If he wants corroboration, let a delegation go. I challenge him. Let him go along with me and see what they felt then and what ihey feel now under Siddhartha Shankar Ray.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): In Kerala, their Government is not there.

SHRl NIREN GHOSH: In Kerala, we are not running the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RA.IU): In Kerala, C.P.M. is in opposition Niren Ghosh need riot actually answer for that Government.

SHRI NIREN GHOSH: Sir, my young friend, N. R. Choudhury, he just said . ..

SHRI N. R. CHOUDHURY: There was no Scheduled Caste Minister.

SHRI NIREN GHOSH: Unfortunately, I do not think that if a person is young, he becomes less intelligent or less knowledgeable. He is ignorant that Shri K. C. Haldar was Minister. He is now a Member of the Lok Sabha. He is a member of our Party and he belongs to the Scheduled Caste. *(Interruption).* My friend does not know even this simple fact.

SHRI N. R. CHOUDHURY : Was he a Minister there ?

SHRI NIREN GHOSH : He was a Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RA.IU): Let us now talk about this Report.

SHRI N. R. CHOUDHURY : The C.P.M. was opposed Io the induction of any Scheduled Caste person in the West Bengal Assembly, but on the insistence of Chief Minister AJoy Mukherjee one man of his Party was included. He is speaking entirely wrong.

SHRI NIREN GHOSH : Sir, I could not follow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAIU) There was no Scheduled Caste Minister in the C.P.(M) Government in Bengal when it was there.

SHRI NIREN GHOSH: I said, I have given the name of the person who was the Minister.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): But on the insistence of AJoy Mukherjee.

SHRI NIREN GHOSH : No. I say it is a lie; it ig a blatant lie.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V B. RAJU): Please now go to the Report

SHRl NIREN GHOSH : He was our . choice, not of AJoy Mukherjee. When those rapes- and murders were going on, he was keeping silent. What is he ? Is he a fellow worth the salt ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B RAJU): Anyhow, no deviation.

SHRI NIREN GHOSH : I do not subscribe to the Congress view. Those who apparently do not say so, hold this view, though not all Congressmen and I am prepared to. absolve you also of that. But the general Congress policy and *he Congress leadership think these are sub-human beings ...

77 RSS/74—5

AN HONOURABLE MEMBER: No. SHRI NIREN GHOSH : .. .otherwise... SHRI KALP NATH: Sir,...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): No please.

SHRI NIREN GHOSH : I would not yield to him. Otherwise, Sir, why could the Scheduled Castes and Tribes people not be given education during these 25 years— free education—to enable them to go to the highest ladder ? I know hundreds and hundreds of Scheduled Castes and Schedul ed Tribes boys who are intelligent but they could not pursue their studies. Cannot education be made free for them to the highest standard ? In these 25 years, thousands would have come up. Lakhs would have come up to fill those posts.

Now, Sir, not only that, there have been instances of atrocities perpetrated on them in Madhya Pradesh, even in your State, Sir, and in Kerala some Scheduled Caste women were raped during this Ministry's regime. This story came up there. That il the treatment that has been meted out to them.

Now, Sir, i3 it not a fact that the land alienation of ihe Scheduled Castes has been the biggest single factor during these 25 years of Congress rule to turn them into beggars ? Mainly they reside in villages. They were engaged in agriculture. They have been forced out of their lands. Lands have been alienated. No land legislations have been implemented by the Congress Government. The so-called legislation has been done with a set purpose of keeping loopholes so lhat the landless labour, the poor labour and precisely those people belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes never get their land. They are thrown out of their lands, which they occupied for generations together. Ultimately now they have been deprived of their. lands. Is it not a fact—Shri A. P. Sharma is sitting there—that in Chhota Nagpur tribal belt, lakhs and lakhs of the people have been uprooted from their lands and no land legislation ever applied to them ?

[Shri Nircii Ghosh]

What about Tripura, Sir? Theic was Land Reservation Act. Tripura tribals were the original inhabitants in certain portions of Tripura.

Now, this Congress Government, after so many years, has done away with that law, so that in the Khasi district or subdivision, whatever you call it, their lands have been grabbed by other people with the covert, overt and open encouragement from the Congress Ministry there. That has been a fact. So I say as regards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes it is primarily a question of lan:l became by far 90 or 95 per cent of them eke out their living either by tilling land *o*<- serving as serves or bonded labour jr by Jboom cultivation or by gathering wood nnd leaves from the forest belt. There have been cases where firing ha; been resorted to and they have been killed. The traditional pattern of getting firewood is from the forest belt, gathering certain leaves and roots for their lives and perhaps also to save whatever cattk- 'hey have at any time. They have been hounded out and firing has been resorted to in many places. This has been the practice. So, Sir, primarily unless they are settled on land, on their own land, nothing can solve this problem. They will never be educated. They wiH never get their dues. If they feel secure on Iand, they can fight for it. Now, they fae! that they are lifeless and they have no place in India. They are destined to die out by serving others as sub-human beings. Now, the monopolists and landlords are within the Congress Government which is anti-Scheduled Castes and anti-Scheduled Tribes. They are anti-peasant, but more particularly they are anti-Scheduled Castes and anti-tribal. That is why they could never get land from the Governments, either Central or State. They hav* not got any land. They constitute six crores. Some day or other their sprouts of eoiis-cience will spring up in them shooting forth and they will try to assert rheir rights. They are being put down killed, murdered, raped, arsoned arid what not. Once they come to their own, once they get consciousness and got organised, a vreitable revolt will start in the countryside and they will teach this Government a lesson which is totally against this section of people.

Now, I would also like to point out tliat the Government has to seriously think whether in these tribal belts, regional council* should not be formed, with extensive rights. They should be composed of the tribal community elected by them with financial resources to settle the land question and the debt question within their region. This is a moot question. If they are entitled to do it regardless of tbe constitutional and other laws, they w'll bo able to assert themselves. So I do propose seriously that in the tribal areas regional councils should be set up with some sort of regional, autonomy, with corrplete powers over education, land, treasury and all those things. They should be vested with sufficient p wers overriding any other legislation, even if they are enshrined in the Constiution. If this regional council decides that the land that has been grabbed by the landlords should be taken away from them withou; paying compensation, that should be granted. If this regional council decides that education should be free un to the highest level, it should not be denied. Then only can they further their objectives. I have a hunch—these higher caste*, the IAS, the ICS and the other adminis-tra;'v; staff, deliberately shut them out so that they can fill in their reserved quota under one pretext or the other, whatever be the percentage. I know—whatever I have said or anybody from this side has said—Shri Kumbhare is not here; otherwise he would have spoken—that perhaps would not be heeded. I would like tht: ouster of this Government. It is a moot question whether the Congress rule will last for ever. It might be that their days are numbered in one way or the other. *(Interruptions).* One does not know. So I say the ouster of the Central Congress

Government and the replacement of it by a government of the workers and the peasants should be there; only then ran a proper solution to this problem be found. Otherwise, these problems will be gelling intensified, will become more acute, and more resentment will come, The writiii? is on the wall for all of us to see about the position of this Government wh'.ch is against six crores of people, which is anti-Scheduled Caste, which is anti-Sch*-duled Tribe, by their total negligent attitude. They maintain even their ca^te system. They encourage the Bhumihars, the Rajputs; they maintain this caste system rigidly. Even in elections they are not allowed sometimes to vote if they, go against a particular Bhumihar, Bajput, this and that. Many Congress Members tell me this in the Lobby. I do not mention their names. So, that is the position. They are held in bondage. They have been denied every possible human right. So, this Government is a double-faced Government. I would say, like bourgeois, they talk one thing and practise another thing. If they say 'garabi hatao', they will grease the palm of the smuggler and create a parallel black money; they will increase the monopolists and make the people poorer and poorer. There was a catch-word in the terrorist days. If a terrorist says •hat he goes to the east, it means that he goes west. It was because they were being hounded out. This Government, whatever it talks, does the opposite of it. If they say clean administration, it means unclean administration. If they say free and fair election, then the election will never be free and fair. If they say, democratic, then it is totalitarian. Exactly opposite is their case. So, the ouster of this Government is the only real solution. Then only this problem of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes will perhaps be solved.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA attar Pradesh): The Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1971-72 and 1972-73 comes to us rather late for discussion, and I would entirely agree with my friend, Shri Deorao Patil that it would be better if, along with the Report the earlier Report and the implementation part of the earlier Report also are placed before us. Sir, (his is a very comprehensive report which deals with a lot of topics such as education, representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the services, about land reform?, land problems, cases of atrocities,. untouchability etc. etc. Certainly, I cannot cover all of them. But I would like to cover so me of the points in the report. First I will take un the question of atrocities.

Sir, yesterday there was published in the Times of India a report about Allahabad. A Harijan, Sevalal of AkVrpur, was assaulted. His house was burnt down. His wife was criminally assaulted by a group of high caste Hindus. There are other reports r!so. I am not going <;*o* take your time. But this is just a story which appeared about my own district, 1 am ashamed to sa.y. Such incidents arc taking place every day.

Again, on 25-7-74 in this House, Shri F H. Mohsin, our Minister informed that in the northern part of the State of Kerala these are certain roads where Harijans are not allowed to walk. They arc prevented fro using certain roads and the State Government, he said, is seized of the question but nothing seems to have been done and the roads continue to be barred to them.

Then, Sir, there is another report g'ven, I believe, by Mr. Mirdha in this very House on 25-7-74 said that members of the Kanbi Pa;el community of the Ran-malpur village in Surendranagar district of Gujarat prevented Harijans from drawing water from the common well and caused darriage to ths earthen pots of the Harijans. Next day there was a row between the Harijan women and some ladies of the Kanbi Patel community. Some men of the Kanbi Patel community armed with Dharies, Lathis, spades and other agricultural implements came to the

[Shri Harsh Deo Malaviya]

spot, overpowered the policemen and forcibly entered the houses of Harijans and assaulted them. Two Harijans died in the incident. This is just one of so many stories.

Then, Sir, in the backward district of Banda, again of my State, the father of a hero of the Indo-Pakistani conflict of 1965 is yet to get possession of 14 bighas of land in Alona village given to his son posthumously, it was alleged that land had been grabbed on extensive scale in the district by upper caste rich and influential people. The Congress MLA., Mr. M. D. Singh, told the U.P. Land. Management Inquiry Committee that land rendered surplus under the ceiling law in Basehri village in his constituency had been given to millionaires of Banda city instead of Harijans. Therefore, this thing has been going on. I can make this list very long but I do not want to take much of your time.

Atrocities are committed on the Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I will take the Scheduled Castes first. The atrocities continue unabated and uncontrolled. All our laws on the subject have failed to prevent the inhuman acts perpetrated on our citizens. I would like to point out that there was a committee appointed by the then Congress President, Dr. Rajendra Prasad, in 1948 under the chairmanship of the great Gandhian, Dr. J. C. Kumarappa. It gave the famous Report of the Congress Agrarian Reforms Committee. In this report special attention was given to the question of agricultural labourers. When the Committee went to Kerala and met some of the agricultural labourers in some northern parts of Kerala in Malabar district, the Chairman askecj them, "Hew do you live ?" And the labourer said :

> "Chakkayum Mangayum Orusingam, Thaluthamaram Orusingam, Angane Ingane Orusingam."

He said that he lives on jackfruit and mangoes in one season, plant leaves in another season, and here and there in the third season. Then, Sir, there is another area in Tamil Nadu. Mayavaram taluka in Tanjore District. The Committee visited that place also. And the "Pannayals" were living there in small places lika the places where dogs live. They were bond slaxes of the "Mirasdars" and their condition continues to remain the same up till today. This report has recorded that when Gandhiji visited Mayavaram ia 1927, he was "constrained to warn the landlords who gathered before him that their lands would grow weeds -md thoros and be barren if no brotherhood of mai was extended to their landless farm servants who were toiling for the health and wealth of their families." , This condition has not changed. This Committee also went to Eastern U.P., to the districts of Gorakhpur, Basti and Ballia, very poor districts. The Committee found that there was a system prevalent in the districts of Gorakhpur and Deoria known as "Gobri". I quote:

> "A Chamar (Harijan) who is employed by a cultivator as *halwaha* is given the privilege of eating the grain in the dung of the bullocks. During threshing the bullocks eat the grain on the threshing-floor and later the undigested grain come out along with their excrement. The Chamars, as part of their wages, are allowed to collect the excre- * ment, dry them and separate the grain which they later use for their food."

These things continue. To our shame we must accept that these things continue in our dear country. As early as 1948, our present Food Minister, Mr. Jagjivan Ram, when he was Minister for Labour, told Parliament "We are losing millions of tons of foodgrains every year because the ill-paid agricultural labourer, who has no stake in land, does not put his heart into work."

SHRI RANBIR SINGH (Haryana): Can you name that particular place where you said "Gobri" was prevalent ?

SHRI HARSH DEO MALAVIYA (Gorakhpur)

का नाम तो याद नहीं है परन्तु अभी भी यह चलता है। कल्पनाथ जी हम जानते हैं यह उसी जिले के रहने वाले हैं । मैंने अपनी आंखों से देखा है मैं झूठ नहीं कह रहा हूं ।

Now, Sir, this Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has given on page 366 the distribution of surplus land in various States. It has just mentioned what ihe ceiling lav/ is and how much ceiling will be fixed on the land. For instance, in regard to Andhra Pradesh it says "Level of ceiling ranging from 4.05 to 21.85 hectares depending upon the quality of the land". Then the next column is "Priority accorded for distribution of surplus land to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe persons". For Andhra Pradesh, it says: "50 per cent of the house sites are to be given to the Scheduled. Castes and Scheduled Tribes and of the remaining, two-thirds are to be allotted to notified Backward Classes." This is just a pious wish. W'hat has been done, nobody knows. We would except this report to be more concrete. These things we know. We know the Acts. We know the legislation. We know there have been so many Acts. But what has been done ? The surplus land all over the country never goes or hardly ever goes or very rarely g^ai to the actual persons for whom it is meant In that respect, I should say that our land reforms are not implemented properly. Their implementation is extremely faulty.

Coming to untouchability, this report has highlighted in a table on page 343 the number of cases dealt with under the Untouchability (Offences) Act of 1955. Here the report gives us very good information. Here the figures are very interesting. The number of cases registered with the Police in 1971 is 526. But the number of cases challaned is nil. How many cases arc challaned ? Nobody knows. The number of convictions is 55, But how many are acquitted ? Nobody knows. These figures are given in respect of several years starting from 1955. The number of cases registered with the police is large, but acquittals are also equally large. Even when offences are registere<l, the cases and taken to courts and people are acquitted. This is not the way how the Untouchability Act should be implemented.

If we are serious about improving the conditions of our Harijans and Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in my opinion, land reform should receive the highest priority. Their exploitation emerges, among other things, from their landless-ness, their proverty and their hunger. They are made to do the dirtiest of works. In this connection 1 would refer to the statement made in this House in reply to Stirred Question No. 215 on 10-5-1973. This statement shows the State-wise Fourth Plan allocations and the amount released during these years in respect of composite schemes for the improvement of working and living conditions of those engaged in unclean professions. The figures for all States are given here. For Andhra Pradesh it is just Rs. 20 lakhs during five years. This is not being just to them. The least that we should do is to stop the practice of human beings carrying the dirt of others. This is a dirty and wretched system. We should certainly have a better sanitary system. Now see, only 20 lakhs are allotted to Andhra Pradesh during the Fourth Plan; Rs. 30 lakhs for Assam; Rs. 20 lakhs for Bihar; Rs. 7 lakhs for Gujarat and Rs. 6 lakhs for Haryana. This is a cruel joke. We ought to be ashamed of it. I would humbly submit that unless we solve the problems of these , down-trodden and oppressed peopl';—oppressed for centuries—who are burning with anger and whose youth are now educated and who are no longer prepared to stand this humiliation which their forefathers suffered, we are going to have civil war in this country. There will be danger of violence and there will be danger of disruption, and Marxists— Shri Niren Ghosh's Party—and Naxalitc*

[Shri Harsh Deo Malaviya]

will exploit this situation to create violence, bloodshed and disaster in this country. Sir, I want to remind the House or what Mr. Chavan said once. *(Time bell rings).* Sir, I will take only a few minutes more and will finish.

3 1'.M.

Sir, Mr. Chavan, when he was our Home Minister, said once—I think it was in 1968 or 1969—that the green revolution might become a red revolution. He gave this warning and he gave this danger signal because he was also aware that the land reforms were not being implemented properly. Now, what happens in east U.P.? Caste conflicts are there in ea?i U.P. The so-called high-caste people are also the richer peasants and th;: so-called lower castes are also the landless labourers. These conflicts these caste conflicts and the class conflicts tend to coincide. Then, what happens? What is the basis of the party of Mr. Charan Singh now ? The party of Mr..Charan Singh, the BLD, is merely playing with the feelings of the lower caste people and so on and in east U.P. . . .

**श्री रबी राय** (उड़ीसा) : हर्षदेव मालवीय जी क्या बोलते हैं, खुद नहीं समझ रहे हैं । बी० एल० डी० कोई एक चरण सिंह जी की पार्टी नहीं है । वह भारतीय लोक दल है, जिसको आप बाकायदा मान्यता दिए हैं । मैं मालवीय जी का पूरा बयान कांटेस्ट करता हूं । ये गलत बोलते हैं । ये बी० एल० डी० के कैरेक्टर को समझे नहीं हैं, उसके कार्यक्रमों और सिद्धांतों को पढ़े ही नहीं हैं ।

**श्री हर्षदेव मालवीय** : हां , आप कृपा करके बैठ जाइये ।

**श्री रबी राय** : बिना पढ़े बोल रहे हैं ।

**श्री हर्षदेव मालवीय** : मैं आपके साथ बैठ कर पढ़ूंगा; चाय पिलाऊंगा और पढ़ूंगा ।

**श्री रबी राय** : बिना समझे बूझे क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, यह कैसे पढ़ेंगे । हम इनको सिखाएंगें ।

*(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Let us confine ourselves to the Report now.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: Sir, 1 will finish in two minutes. I have not been talking anything irrelevant. *Ia* east U.P there is a saying:

"बाम्हन, छत्री लाला
इनका मुंह कर दो काला
इनको दे दो देश निकाला ।"

It means : Blacken the face of the Brshmin, the Kshatriya and the Lala and exile them.

SHRI MAHAVIR TYAGI (Uttar Pradesh) : You are also a Brahmin.

SHRI HARSH DEO MALAVIYA: हां मैं बाह्मण हूं । यह आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है और रबी राय के लिए भी है । Sir, my time is up and I will finish in two minutes. I have been talking about the Scheduled Castes. Now, Sir, I will refer to the Scheduled Tribes. There is a Report, the Twenty-first Report of the Fifth Lok Sabha, the Report of the Committee oil the Welfare of the Scheduled Castes. Many honourable Members silting in this House are members of this Committee. For example, hon. Mr. N. P. Choudhury is a member of this Committee. This Report was presented on 3rd May, 1974. Sir, this Report makes a painful reading. I will just read out two or three passages from this and I will finish.

This is about Arunachal Pradesh and this is after a thorough study of the tribal area :

"The Committee are distressed to note the very low percentage of literacy not only among the Scheduled Castes, but also amongst the general population in Arunachal Pradesh . . . The Committee are unhappy to note that the boys who reside at a distance of less than 8

kilometres from their schools and tbe girls residing at a distance of less than 5 kilometres from their schools are not admitted in the hostels ..."

The Report further says:

"The Committee regret to observe that no land reforms worth the name have been initiated in Arunachal Fradesh. The Committee also a/e unhappy to be informed that the Scheduled Tribes in Arunachal Pradesh are facing difficulties in getting loans from the State Bank of India in the absence of any document relating to occu^nncy. In the circumstances, the Committee hardly need to emphasise the necessity for the proper maintenance of land records. The Committee suggest that, to begin with, all certificates of occupancy to the Scheduled Tribes should be given on a priority basis to enable them to secure loans from the State Bank of India."

Then, Sir, I will read out the last quotation:

"The Committee are unhappy to be informed that out of a total of 2,973 villages in Arunachal Pradesh, only about 460 villages have been pr J /ided with drinking water. There are no modern hospitals . . . The Committee regret to observe that in spite of there being vast potentialities for setting up of industries, no serious attempt has been made to industrialise Arunachal Pradesh, Though various technical teams have submitted feasibility reports for setting up harvest-based and agro-based industries in Arunachal Pradesh, the Government has adopted a policy of drift and indecision resulting in enormous delay in this regard ..."

In conclusion, Sir, I will submit that this Report is good enough. It is a very big Report. There is a lot of stuff. A lot of money is being spent, etc. etc. So this Report should be taken more seriously. I would appeal to the Minister to take into consideration not only what has been said in this House but also what has been said in the various reports of the Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. They have been giving very useful reports if you see through the reports. This should not remain on paper only, but it should be implemented. If it is not implemented, let me warn you that the Harijan young men, the educated young men be'onging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, will not take it lying down; they are in a mood to fight. And they will fight. We have to unite to save them and save our country . . .

*(Interruptions)*

श्री रबी राय: उपसभाध्यक्ष महोदय, आज जिस रिपोर्ट के ऊपर हम बहस कर रहे हैं, उस पर बहस करने से पहिले मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की रपट की बात हम लोग करते ही हैं और हम लोगों का ध्यान इसी पर ही न रह जाय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि हरिजन और आदिवासियों के अलावा हमारे देश में एक पिछड़ा हुआ वर्ग है, जिसकी ओर भी हमें ध्यान देना है । उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो बहुत पुराने आदमी हैं और आप जानते हैं कि पिछड़े हुए वर्ग और पिछड़ी हुई जातियों के साथ ही साथ कुछ इस देश में पिछड़े हुए वर्ग भी हैं, जिनके बारे में एक कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने इस वर्ग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट दी है, जिसका नाम काका कालेलकर रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को सरकार ने पिछले 10--15 सालों से अपने पास रखा हुआ है और उसने सदन के सामने उसको पेश नहीं किया है । काका कालेलकर कमीशन की जो रिपोर्ट बैकवर्ड क्लास वाले लोगों के सम्बन्ध में थी, उसके बारे में, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार को उसके सम्बन्ध में सदन में बहस करवानी चाहिये । मैं मंत्री जी से और सरकार से मांग करूंगा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट पर सदन में बहस होनी चाहिये ताकि इस बारे में हम लोगों की राय भी सरकार को मालूम हो

[श्री रवी राय]

इसके और सदन की राय भी इस बारे में सरकार को प्राप्त हो सके। इस रिपोर्ट पर बहस करने से हम हरिजन और आदिवासियों के साथ ही साथ जो करोड़ों पिछड़े हुए लोग हमारे देश में हैं, उनकी स्थिति के बारे में हम जान सकेंगे।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि आज भी हमारे सदन में एक सदस्य हैं जो काका कालेलकर कमीशन के सदस्य रह चुके हैं। वे आज भी इस सदन के सदस्य हैं। इसलिए मेरी पहिली मांग यह है कि इस कमीशन की रिपोर्ट पर सदन में पहिले बहस का मौका दिया जाना चाहिये।

इसके बाद मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो रिपोर्ट है, वह एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। संविधान में कमिश्नर की नियुक्ति के बारे में कहा गया है और उसके ऊपर इन लोगों की जिम्मेदारी डाली गई है ताकि वह देश के सामने और सदन के सामने हरिजन और आदिवासियों की दशा के बारे में अपनी रिपोर्ट और सिफारिश दे। मैं पहले यह अर्ज करना चाहता हूं कि आजादी के बाद मैं दो युग मानता हूं। एक तो गान्धी जी का युग और दूसरा उनके देहान्त के बाद श्री जवाहरलाल नेहरू का युग। नेहरू जी के युग में यह सरकार चली। इसलिये मैं आज इन दो युगों के बारे में कहना चाहता हूं। गौतम बुद्ध के बाद इस देश में गान्धी जी पहिले आदमी थे जो कास्टिज्म और जातिवाद के खिलाफ थे। अगर हिन्दुस्तान में कभी भी इस तरह की लड़ाई लड़ी गई तो पहिले गौतम बुद्ध ने यह लड़ाई लड़ी और उसके बाद महात्मा गान्धी जी ने लड़ी। मैं जिस माहौल की बात आपके सामने करना चाहता हूं वह गान्धी जी का जमाना था और आपको याद होगा कि गान्धी जी केवल हरिजनों के ही बारे में सोचते थे और उनकी ही बात करते थे। हरिजनों के सम्बन्ध में गान्धी जी का जो चिन्तन था वह आजादी के बाद कार्यान्वित होगा और वह दिन आयेगा जब गांधी जी का वह स्वपन साकार होगा जो वह यह सोचते थे कि कोई हरिजन लड़की भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होगी। लेकिन यह सरकारी दल जो 28 सालों से देश में राज्य कर रहा है उसने गान्धी जी की जो सोच थी इस बारे में, उस तरह के दृष्टिकोण की कमी है। गान्धी जी का इस बारे में जो सोच था उस तरह का सोच शासक दल का नहीं रहा है और 28 सालों से शासक दल अलग तरह से सोच कर रहा है। मैं आपको उस माहौल की याद दिलाना चाहता हूं कि जब गान्धी जी हरिजनों के बारे में लड़ रहे थे तो सनातनधर्मी हिन्दू क्या कर रहे थे। वे आज भी कांग्रेस दल के अन्दर मौजूद हैं। आन्ध्र प्रदेश में, आपके प्रान्त में थिम्मा रेड्डी साहब कृषि मंत्री थे। हरिजनों के बारे में उन्होंने जिस तरह के अपशब्द कहे थे लोक सभा के सदस्य के नाते मैंने उस पर बहस उठाई थी। गृह मंत्री ने भी इस बात को माना कि थिम्मा रेड्डी को, जिन्होंने संविधान के प्रति शपथ ली थी और जो मंत्री थे, हरिजनों के प्रति इस प्रकार के अपशब्द नहीं कहने चाहिए थे। गांधी जी का एक वाक्य पढ़ कर मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह माहौल हम देश में पैदा कर पाएंगे ताकि हिन्दुस्तान में जितने पिछड़े हैं, जितने गरीब हैं, आदिवासी हैं, हरिजन हैं उनके अन्दर आत्म-विश्वास जग सके। इस सरकार की सहायता से उनके मन के अन्दर विश्वास नहीं पैदा होगा। उनके मन के अन्दर एक फौलादी आत्म-विश्वास जगाना होगा और तभी हरिजनों का, पिछड़े हुए लोगों का हम कल्याण कर पाएंगे। सनातनी लोगों को जवाब देते हुए गांधी जी ने कहा था—

"Let me tell the Sanatanists who claim to be monopolists of religious truth that I believe in the same Shastras as they do. I have profound disagreements with ihern as regards the interpretation of these Shastras which lay down that, when there is a conflict of interpretation, one must follow the promptings of one's own conscience, and that is exactly what I am doing. I would be the Sanatanists' slave if they could convince me that I was wrong. Meanwhile, I will say even with my last breath that

if wa do uot wash out the stain of untouchability, Hindus and Hinduism will be wiped out from the face of tha earth."

far *

"And yet our woebegone Indian society has branded the Bhangi as a social Pariah, set him down at the bottom of the scale, held him fit only to receive kicks and abuse, a creature who must subsist on the leavings of the caste people and dwell on the dungheap. He is without a friend, his very name has become a term of reproach. This is shocking. It is perhaps useless to seek the why and wherefore of it. I certainly am unaware of the origin of the inhuman conduct, but 1 know this much that by looking down upon the Bhangi we—Hindus, Musalmans, Christians and all—have deserved the contempt of the whole world. Our villages have today become seats of dirt and insanitation, and the villagers come to an early and untimely death. If only we had given due recognition to the status of the Bhangi as equal to that of a Brahamana as in fact and justice he deserves, our villages today no less than their inhabitants would have looked a picture of cleanliness and order. We would have to a larjze extent been free from the ravages of a host of diseases which directly spring from our un-cleanliness and lack of sanitary habits."

ये दो उद्धरण मैंने आपकी खिदमत में पढ़े; क्योंकि वह माहौल आपको लाना है जिससे हरिजन, आदिवासी, गिरिजन, वनवासी जो गरीब हैं, जिनका चारों तरफ से शोषण किया जा रहा है, छोटी जाति में पैदा होने पर और बाद में आर्थिक ढंग से, उनका उचित विकास हो सके। अभी वह माहौल नहीं है। जयप्रकाश नारायण कुछ उस माहौल की तरफ ध्यान खींच रहे हैं। हम चाहते हैं कि जयप्रकाश जी जो कोशिश कर रहे हैं वह जारी रहे। इस रिपोर्ट में कहा है—

Sir, I quotes.

"In a village in Saharsa district in Bihar, four Scheduled Caste ladies were stripped naked and branded all over their bodies with red hot iron sickles, the worst part of the whole episode being the fact that this heinous crime took place in the presence of a large number of non-Scheduled Caste persons, including children—none coming forward to protest against the inhuman and dastardly crime.

Equally unfortunate was the case of two Scheduled Caste women in a village in Parabhani district in Maharashtra, who were stripped naked by a landlord and his servants on their begging for drinking water to quench their thirst."

यह कमीशन की रिपोर्ट है। मैं कहना चाहता हूं श्रीम मेहता साहब से कि पिछले सत्र में गुजरात के ऊपर चर्चा हुई थी। मेरा तो नाम उसमें था लेकिन कांग्रेस के एक सदस्य मकवाना साहब थे उन्होंने बताया। गांधी जी का वह इलाका है, जिस तरह से वहां पर हरिजनों पर अत्याचार हो रहा है, किस तरह से महाराष्ट्र और बिहार में अत्याचार हो रहा है वह आपको सुनाया। कहां हम लोग जा रहे हैं? कहां यह देश जा रहा है। यह सवाल है कि देश किस तरफ जा रहा है। श्रीम मेहता साहब कहेंगे कि मैंने तो रिपोर्ट दे दिया। सरकार बहुत कोशिश कर रही है। लेकिन कोशिश आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है। गांधी जी का जो आह्वान था जिसका हमने समर्थन किया था, उस भंगी के बारे में कोई परिवर्तन आज देश में नहीं हुआ सिवाय इसके कि कांग्रेस ने हरिजनों और आदिवासियों का फायदा उठा कर वोट को सुरक्षित किया है। इतना ही हुआ है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की आजादी के बाद दो आदमियों का नाम मैं लेना चाहता हूं जिन्होंने इस बारे में बुनियादी ढंग से सोचा। एक थे डा० अम्बेदकर। भले ही कांग्रेस के लोग उनको नेता न मानें, लेकिन हिन्दुस्तान के तमाम पिछड़े हुए लोग, वनवासी, हरिजन, गिरिजन और आदिवासी आज भी यह मानते हैं कि वह एक तेजस्वी नेता थे। इसी तरह से मैं डा० राम मनोहर लोहिया का नाम लेना चाहता हूं। परसों

[श्री रवी राय]

श्री भोला पासवान जी बोल रहे थे कि डा० लोहिया के चलते मैं बिहार का मुख्य मंत्री बन पाया था। यह सही है कि हरिजनों को आपने दया का और सहानुभूति का पात्र बना दिया है। लेकिन आज सवाल यह है कि 22 करोड़ हिन्दुस्तान में हरिजन बात करते हैं और उनको आप दया का पात्र बना देते हैं तो फिर उनके दिमाग में यह आ जाता है कि हम शासन में जाने लायक नहीं हैं। कहा गया गांधी जी का वह सोच कि हिन्दुस्तान में एक दिन वह भी आयेगा जब राष्ट्रपति के पद के लिए हम किसी हरिजन को बैठा देंगे। यह तो एक प्रेक्टिकल आइडियालिज्म था, जिस पर गांधी जी सोचते थे और उस दिशा में काम करते थे।

आप देखेंगे कि हर एक स्तर पर रिजर्वेशन का सवाल ले लीजिये, अनटचेबिलिटी का सवाल ले लिजिये, यह सरकार 28 साल से इन बुराइयों को दूर करने में असफल रही है। यह सरकार के दिमाग में तनिक भी सोच होता तो हम लोग इसमें असफल रहते ? हरिजनों को ऊंचा उठाने में हम असफल रहे हैं। क्यों असफल रहे हैं, इसलिये मैं बुनियादी तत्वों में जाना चाहता हूं कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है। इस सरकार का कोई दिग्दर्शन नहीं है। क्या दिग्दर्शन रहना चाहिये जाति प्रथा को खत्म करने के लिये। यह गांधी जी ने कहा था कि कास्ट के सिन को और अनटचेबिलिटी के सिन को खत्म करना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय को जो चलाते हैं, इस सरकार को जो चलाते हैं यह सरकारी दल जो है क्या इसके दिमाग में यह सोच है कि कास्ट सिस्टम नष्ट हो ? अनटचेबिलिटी को कौन खत्म करेगा क्या हुआ ? मैं आपको इस रिपोर्ट से पढ़ कर सुनाना चाहता हूं कि यह तो ऐसी खतरनाक चीज है कि इस सरकार को एक क्षण भी इस गद्दी पर नहीं रहना चाहिये। खुद कमिश्नर साहब लिखते ह कि एक कमेटी बैठाई जाए। एक कमेटी बैठाई गई थी। 1972 के बाद जो संरक्षण मिलता है, रिजर्वेशन मिलता है वह कार्यान्वयन में है या नहीं, इसके बारे में कमीशन के पास आपत्तियां आनी चाहिएं। कमीशनर खुद लिखता है कि हमारे पास तो कई-कई हरिजनों ने शिकायतें भेजी हैं, लेकिन उसे कार्यान्वियन करने का हक हमारा नहीं है। हमारी शक्ति नहीं है। कहते हैं :

J. hare is no doubt tbat during the course of investigation*, the Scheduled Caste/Tribe persona concerned do get justice if any breach of rules is found. If, therefore, in spite of the above statement of the Minister for Education and Social Welfare, made in Parliament, the decision of the Committee of Secretaries "—to whom the matter has been referred—" is not in favour of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes calling for relevant records for examination of cases of alleged violation of rules and regulations issued in connection with the service safeguards for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the only course left to the Commissioner will be to give up the examination of such cases, as in such a case he will not be in a position to do full justice while investigating into cases of alleged injustice in service matters brought to his notice by the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Government employees. The best course in that case would be to amend article 338 of the Constitution under which the Commissioner's appointment has been made by the President, to make it clear that the Commissioner would investigate into safeguards provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Constitution, other than those indicated in articles 16(4), 320(4) and 335 of the Constitution."

सवाल यह है कि उपाध्यक्ष महोदय मान लीजिए कि जो संरक्षण विधान में है उस पर कार्यान्वियन नहीं होता है तो बेचारे हरिजन, आदिवासी कहां जाएंगे। कमीश्नर निरपेक्ष आदमी है। वह खुद मानता है कि हम को अधिकार नहीं है। हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिये कहते हैं कि संविधान में परिवर्तन करें ताकि कमीश्नर भी इस शिकायत को देख पाए और जो उसके लिए दोषी हो उनको दंड दे पाएं, मैं यह चाहता हूं कि इसके बारे में भी आप सोचें।

इसी सिलसिले में मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि हरिजन आदियासियों के लिए आपके दिमाग में क्या गड़बड़ है जो इसको कार्यान्वियन नहीं किया गया है। एक सिद्धांत की बात मैं आपको बतलाता हूं। सिद्धांत

की बात यह है कि हम लोग समान अवसर की बात मानते हैं। यह चीज आप रूस क्रांति और फ्रेंच क्रांति से उधार लाए हैं। आपने यही सीखा है कि सब को समान अवसर दो। ब्राह्मण को समान अवसर दो, कायस्थ को समान अवसर दो। समान अवसर के सिद्धांत का शिकार कांग्रेस दल हुआ है। मेरा आपसे कहना है कि हिन्दुस्तान के अन्दर अब यह समान अवसर वाली बात नहीं चलने वाली है; क्योंकि देश में जाति प्रथा है। यूरोप में नहीं है। देश में कास्टीज्म है। इसलिए हम मानते हैं यह समान अवसर की बात गैर-क्रांतिकारी है, प्रतिक्रियावादीसिद्धांत है। आपको इनको स्पैशल अपोर्चुनिटी देनी चाहिये, स्पैशल अवसर देने चाहिये। हजारों पिछड़े, आदिमजाति लोगों को राज्यों की नौकरियों में आगे आने के लिये अवसर दें। मैं बताना चाहता हूं कि चार विशेष स्थान हैं, उनमें आपको इनको प्रियोरिटी देनी चाहिये। राजनीति दलों में भी हिन्दुस्तान के हर राजनीतिक दल अनुपात के हिसाब से लिये जाएं।

**श्री एन० आर० चौधरी** : रबी राय जी आपकी पार्टी में कितने आदिवासी हैं?

**श्री रबी राय** : हमारी पार्टी का नियम है कि कार्यकारिणी में 60 प्रतिशत पिछड़े और हरिजन आदिवासी रहेंगे।

*(Interruptions)*

**श्री एन०पी० चौधरी** : राज्य सभा में कितने हैं?

**श्री रबी राय** : मैं पूछना चाहता हूं कि दल बड़ा है या राज्य सभा के मेंम्बर बड़े हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Please sit down, Choudhuryji

**श्री रबी राय** : हरिजन औरतों को रैप किया जाता है। यह कमीश्नर कहता है। कौन जिम्मेदार है इसके लिये। हरिजनों को बलात्कार कौन करता है इस सब का जवाब नहीं आता है। मैं यह कह रहा था कि भारतीय लोक दल ने हमारे सिद्धान्त को मान लिया है. . . . . .

**श्री कल्प नाथ** : मेरा पौइन्ट आफ आर्डर है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय लोक दल ने 60 परसेन्ट का सिद्धान्त अपने दल में लागू कर दिया है?

**उपसभाध्यक्ष (श्री वी० वी० राजू)** : यह कोई पोइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

**श्री रबी राय** : मेरे पास यह वक्तव्य है, आप जरा इसको पढ़ लीजिये। जो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का 60 परसेंट का सिद्धान्त था वह बी०एल०डी० में बरकरार है, यह बात आपको जान लेनी चाहिये। डा० राममनोहर लोहिया का यह बुनियादी सवाल था कि जाति प्रथा को समाप्त किया जाए और इसके लिये हमें विशेष अवसरों के सिद्धान्त को लेना चाहिये। विशेष अवसरों में चार बातें आती हैं। आई० ए० एस० और आई० एफ० एस० में इन जातियों को सबसे अधिक प्रतिनिधित्व, राजनैतिक दलों में नेतृत्व, व्यापार व्यवसाय में नेतृत्व और मिलिट्री में इनको स्थान देना, ये चार पहिये हैं, जिनके आधार पर किसी समाज का संचालन होता है। नेतृत्व अगर ब्राह्मण के हाथ में होगा तो समाज में जो हरिजन हैं या पिछड़ी जातियां हैं उनको वे दया की दृष्टि से देखते हैं। यह कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिये मैं सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि डा० अम्बेदकर के शिष्यों ने जो दलित पैन्थर नाम से संस्था बनाई है, वह इस बात का प्रतीक है कि अब इन नवजवानों में आत्मविश्वास आ गया है और वे अब दया के पात्र नहीं बनना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में आप केवल यह कह दें कि हमने यह रिपोर्ट दे दी है और हम अमुक काम कर रहे हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। आपने इस रिपोर्ट में कहा है कि जो यूनियन टेरेटरीज हैं, जैसे अन्दमान निकोबार है, वहां पर इन जातियों को प्रमोशन और नौकरियों में जो संरक्षण प्राप्त थे और जो उनके लिये रिजर्वेशन था, वह पूरा नहीं हो रहा है। आप, इस बात को जानते हैं कि जाति प्रथा को समाप्त करने के लिये गांधी जी ने बहुत जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि अन्तर-जातीय विवाह हों। गांधी जी ने यह भी कहा था कि मैं उसी शादी में जाऊंगा जहां एक हरिजन लड़की किसी ब्राह्मण के लड़के से शादी करे या इसका वाइसवर्सा हो। उनके देहान्त के बाद जिस तरीके से इस अन्तर-जातीय विवाह का प्रचलन किया जाना चाहिये, वह नहीं हो रहा है। इस दिशा में मैं तामिलनाडु की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तामिलनाडु सरकार की ओर से यह आदेश निकाला गया है कि जो व्यक्ति अन्तर-जातीय विवाह करेंगे और इस प्रकार से हरिजनों की लड़कियों से शादी करेंगे, उनको बजीफे दिये जाएंगे। अन्त में मैं

[श्री रवी राव]

कमिश्नर की रिपोर्ट से यह रिकमेन्डेशन पढ़ना चाहता हूं :—

"Some of the steps taken by the State Governments of Gujarat, Kerala, Maharashtra and Tamil Nadu in this regard are commendable...."

इस बारे में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को छोड़कर जो दूसरी स्टेटें हैं उनमें उन लोगों को प्रमोशन देने के बारे में कोई कार्यवाई नहीं की गई है जो इस प्रकार से अन्तर-जातीय विवाह करते हैं। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि :—

"but there is need to further encourage the inter-caste married couples by assuring them that their children would get free education at all stages regardless of the income of the family. At the same time, it is necessary that inter-caste married couples should be given preference in the matter of recruitment to Government posts, allotment of land, house sites and houses so that these symbols of a casteless society are given due recognition by the nation."

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर एक कास्टलैस और क्लासलैस सोसायटी स्थापित करने के लिये आप बुनियादी ढंग से सोचें और यह जो रिपोर्ट है और इसमें जो सिफारिशें की गई हैं उनको कार्यान्वित करें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. B. RAJU): Mr. Panda.

SHRI NIREN GHOSE: Sir, he cannot speak. His duty is to see that people go to heaven and not to hell.

THE VICE-CHAIRMAN : (SHRI V. B. RAJU) : Mr. Niren Ghose, please hear him.

SHRI BRAHMANANDA PANDA ^(.Orissa): If he wants to go to hell, I have no objection.

SHRI N. P. CHAUDHARI: He is a modern Panda.

SHRl NIR1N GHOSE: TUn h* *QMU* speak.

SHRl BRAHMANANDA PANDA: Mr. Vice-Chairman, Sir, you will have observed that when this report comes for discussion in this House the difference on both sides, the ruling party and the opposition, nar-IOWS down to the barest minimum. That is because this is a problem that concerns the life of the Adivasis and Harijans in the country and it perturbs everybody. It touches everybody's conscience and with whatever is being done, even if more and more is being done every year for the amelioration of their lot* we do not feel satisfied. There is a reason also because although the Commissioner bas done a very good job and it is a very comprehensive and good report, we simply close the chapter there. We give him congratulations and thanks and the onus of implementing these things lie with the State Governments. From the Central Government many times reminders and other things go, but they do not care to reply. They do not care to follow the guidelines from the Centre given from time to time. I come from a novmc. which can really be termed an Adivasi province. You will be interested to knew tbat the present Lord Jagannath, become famous throughout the world and considered to be the most important God of Oriyas, was formerly a tribal chief's God. Jagannath was formely known as 'Neel Madhao' and worshipped by a tribal chief. The then king of Orissa, through treachery, carried away the chieftain's God. He placed Him at Puri as Lord Jagannath and with that he snatched his land also. You, Sir, know that during Panditji's time your State gave us the first Harijan Chief Minister and the late lamented Sanjivayya not only proved himself to be a very important and competent Chief Minister but as a Congress President also I have seen few people who were so gen-ST0US. Why not during Mrs. Indira Gandhi's time Orissa give to the eountry an Adivasi Chief Minister? Sir, what is the lot of Adivasis today ? During the last general elections I had been to the Adivasi areas.

I had been to many village*. In one village in my district of Ganjam a Harijan lady about the age of 75, after my meeting was over, came and patted my cheeks. Giving her blessings, she said: Son, you take my longevity and live long, but do not forget us. When I think of them today I feel like a criminal. She was 75 and she could have been my grandmother. She is actually my grandmother. If I think of them now I feel I am a criminal. Today the people of Orissa are facing hunger. Orissa has had an unprecedented drought this year and in Ganjam my home district, which is considered to be one of the granaries of Orissa, you go to the villages today. There people have begun to die. Although reports do not come, by March and April next, the food position will be *o worse that hundreds of Adivasis and Harijans are bound to die. Give it any name as you please. Call it malnutrition, gi!sl:o-enteritis or because of weakness oiher diseases have accrued in him for the last so many years, but starvation will dunce naked in the streets of Orissa within a couple of months or after three months. In the Mayurbhanj district the Adivasis and collect honey. With all our promise from the Centre and the management that was done by the Orissa Government, rice vould not reach the Adivasi belt.

They had to exchange one kg. of honey for one kg. of rice. The middlemen exploited them. And with that one kg. families have to be sustained for days and days together. They eat roots; they eat leaves. And I have seen Adivasi families who sim ply boil this green pepper and eat it as their food. This is the position of the Adivasis in the different areas. And Orissa is the worst sufferer. And these are the very people who have voted us into power. I t<-ll you—and I repeat—I feel myself a criminal because I had given them a promise that we will not forget them, that they are the base, that they have voted us into power. But after coming to power, again, the Mahapatras, the Pandas, the H'adhans, the Dasses and the Mahantis are ruling the State. *(Interruptions).* Our verbal sympathies and our crocodile tears will not help them. After all, are they not the citizens of this country 7 Here everyone has got vote. Sir, you who are sitting in that great Chair have got one vote also. Simp-by because we know how to talk and speak jocularly and say things with a little flavour, that will not help them. Actually, power has to go into their hands. I may not agree with Shri Rabi Ray cent per cent. Hut on one thing I agree transfer ot power to their hands—we go *to* him, we take his vote and come away, and we say that we are always with him. But we are not going to transfer power to them. And what will the Centre do ? The real thing remains at the State level. And at the State level these very people are exploited. I will give ycu one example. When there was the Naxalite trouble in a small town in Koraput District, some CRP men were posted. It was a place cut off from civilisation. So, for their rations, they could not get chickens and other things. And they went into the hinterland, into the interior, and snatched whatever these Adivasis had with them, chicken. That was a town to be protected, to small town. Who were to be protected? The Komutti merchants. To protect the Komutti merchants, we sent some armed constables but they stayed there and exploited the Adivasis. So, naturally the Naxalites got more shelter among the Adivasis than in other areas. This is the situation. We exploit them politically and culturally and also socially: and exploitation financially is the common thing. You know the bethi begari system and how the Mahajans operate this chakravriddhisud, that is the compound interest system. That is still going on in Orissa. But nothing has been done to ameliorate their lot.

I was going through the Report. There is a tribal block in Gunupur in the District of Koraput. The report is about what has oeen done. What is the tangible result when the. Commissioner writes to them? No reply comes from any State Government. I served on that Committee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes when my frierd, Mr. Buta Singh, was the Chairman. And I know what heart-burn he and I had. Mr. Buta Singh is a Sikh.

{Shri Brahmananda Panda]

The Sikhs have no caste system. But he had been treated as a Harijan as before. If that is the society we are living in and if we are thinking that we will help these down-trodden people, these people who are being crushed under our feet, and we want to bring them to light, it is not possible unless we transfer power into their hands. Let them manage their own affairs; we will be their guides. We can tell them if they go wrong, we can advise them. But the real power must come to them. Otherwise, there can be no solution foi them and there can be no hope for them. In Narayanapatna in Koraput District, there is a multipurpose tribal block. Lakhs have been bungled there. When there was President's rule there—Shri Jatti was the Governor—at a flood Committee meeting voiced their complaints, grievances, against the BDO and the civil-overseer. These two persons, the BDO and the overseer, combined and embezzled about five to seven lakhs of rupees.

The people who complained went to the Tehsildar, went to the Collector and to other places but nobody heeded. At last they sent me a letter through one of my relatives who lives there. They said that roads had been constructed only on paper, that wells had been dug only on paper and pigs to the Harijans had been supplied only on paper. So many officers have been going there. The Collector was going, the Commissioner was going, the Ministers were going and getting garlands but nobody looked after their cotnplaints. During the President's Rule in Orissa I raised the question before the Governor, Mr. B. D. Jatti, in a Flood Committee meeting. He immediately took interest and ordered an enquiry. I do not know what happened later. When I met the same relative some time ago he said everything had been covered up and now the position is that the B.D.O. who was the main man to exploit these people has been promoted to a higher post. And this happens in every State. Therefore, I would appeal to the Harijan and Adivasi legislators of Orissa for some time to forget their party differences and to get united to see that an Adivasi is rlected a3 the Chief Minister. Then only ihey will understand how they are being exploited. They will understand the difficulties they have to face. Now-a-days when we go to them we go to them for a prati-cular purpose, namely, to catch their votes. I will not go deep into the matter. The more I go deep my friend, Mr. Om Mehta, may not like it. Personally he likes me. Placing my hand on my conscience I cannot say that we are doing adequately for the Adivasis and Harijans.

Who are these Adivasis ? Simply be cause they live in the forest, half-naked and like half men, do not think they have always been like that. The Adivasis have a rich heritage. They are the inheritors of a great culture, a great civilisation. In the recent archaeologicr.i finds you will see that whether it is in Latin America, Europe, Asia or Africa, man goes back beyond 30,000 years. After the publication of Peri Reiss maps it is found that ia Turkey a great civilisation was flourishing twenty thousand years ago. They had an idea of electricity. They had an idea of the atom. They had astronomical observatories. They had an urban system of life which, we are not in a position to build up even now with all the money at our disposal. Before you ring the bell I wiU wind *v.p.* So Sir, the Adivasis must be allowed to know that he is not a head-hunter or a cannibal or a naked man living in the jungles, he should be proud that is the inheritor of a great Civilisation, descendant of a flourishing culture. So I would request the Home Ministry to put more money for research *to* let them know who they are, to let them know for how many thousand years they had built up a civilisation. You will be interested to know that the present Lord Jagannath, formerly known as Neel Madhao, was a tribal god. He was worshipped by a tribal chieftain from whom the then King of Puri, through treachery, snatched away the god and his land so. Ten thousand years ago when we were nowhere in the picture,

and the Aryans had not thought of migrating from Asia Minor, the Adivasis had a rich civilisation. Others snatched away their lands and their gods and effaced their civilisation. We have now given them begging bowls to stand before us and ask for crumbs.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI OM MEHTA): Sir, it is only for this reason, that a Scheduled Tribes man from Orissa has been included in the Central Cabinet.

SHRI BRAHMANANDA PANDA: I am »ery happy you have done it here. But what about a man there ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRl V. B. RAJU): So his speech^ was anticipated. Mr. Goray.

SHRI N. G. GORAY: Sir, whenever we discuss the Report, I think the important point that has to be borne in mind is how we look at this Report. Do we look at this Report as an opportunity to shed tears over the lot of the Harijans and the Girijans every year and then forget about it during the remaining 11 months ? On do we look at it as a sort of charge-theet not only against the Government— I would not say that—but also against the entire social structure that we inherited and which we are maintaining ? Sir, I look at it from the second point of view. The temptation, of course, is there to accuse the Government, but it is not the Government only which is exploiting the Adivasis but the entire social system which the Governmeat as well as the Opposition represent. So, I really congratulate the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for presenting to this House a very detailed report. It is a good report, it is an exhaustive report and I should like to add that it has been written with real sympathy for the Harijans and the Girijans. It has given instance after instance to show how the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are being treated. I do not want to quote exhaustively, but I would like to point out one or two cases, which will conclusively prove that it is not only a particular person or a particular class which is perpetuating this inequality, this persecution, but it is the entire outlook of our society. Here on page 2, the Commissioner has pointed out a case in which a Scheduled Caste Lecturer was married to a Jat lady. Sir, it was not the common people in the streets of Punjab or Haryana who rose against tt, but it was the Head of the Department who took action, and that Lecturer was dismissed from service. And it was intervention from the top. . .

I

SHRI OM MEHTA : On the Prime -Minister's intervention he was reinstated.

SHRI N. C. GORAY : I am giving compliments where they are due. I have no allergy to the Prime Minister as some others may have. I have no allergy at all. But it really shows the spirit with which we are dealing with this problem. Why should ihe Prime Minister have to in tervene? Because no other intervention, no other logic, no other reasoning, could pre vail. It was only after the intervention of the Prime Minister that the whole thing was restored to normal. Another instance which the Commissioner has pointed out—so many instances are there—is about an incident which happened in Maharashtra, a land of saints, Gyaneshwar, Tukaram, and Eknath. There two Harijan women were stripped naked. The most important part or the most painful part of the whole story is that the Commissioner has gone on re cord to say that "instead of condemening such a shameful act, a lady Member of Parliament asked the Commissioner to find out also about the character of those wo men, thereby attributing the incident to their possible loose character." I do not want to say who that lady was though I can very well guess____

SHRI N. G. GORAY: Unfortunately she lady is no more a Member of Parliament now.

SHRI N. G. GORAY : Unfotunately she was here for the last five or ten years.

SHRI OM MEHTA: She was from the Congress Party and that is why a ticket was denied to her.

SHRI N. G. GORAY : That is not the point I am driving at. Even a Member of Parliament, instead of sympathising with those women and really being angry with those who had stripped those women naked, asked whether those women had a loose character implying thereby that if their character was loose, they deserved it. That is why I say that in the whole of our society our values are caste-based. If a women belonging to an upper class « raped, there is lot of furore and shouting, this and that and perhaps even venge. But if a women belonging to a lower caste oi if a Harijan woman or Adivasi woman is raped, it wilKbe said that it always happens like that- This is the whole attitude and that is. exactly the root of the matter. This can be eradicated, if all of us, as my friend Shri Panda pointed out, join together and we consider it as our primary duty tu see to it that human rights are restored to those whom we consider as citizens of India. Constitutionally they are citizens of India. But in practice they are not. They are worse than the Negroes in America. That is my contention. This can only be remedied if all of us are to put our energies, resources and efforts together to see to it that they are treated as human beings. That is the first thing.

In this report you will find that very great importance has been given to education that we are imparting to these H3ii-jans and Adivasis. I agree that unless the children of Scheduled Castes and Tribes get proper education, it will not be possible for them to reach the levels which others have reached and unless a sort of equality in education and competence is established, always we will look down upon them and they shall have a sense of inferiority. In so far as education is concerned, the figures quoted here are very eloquent. Speaking about Maharashtra, the Commissioner on page 57 of his report has said that the enrolment of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the State, which is encouraging at primary level, viz., 64 per cent, drops sharply to 16 per cent at the middle level. Thus there is about 75 pei cent wastage of education at the middle level. This is a very serious matter. If this happens in Maharashtra, much worse must be happening in other States. You will find that at the primary level in Maharashtra there is 64 per cent enrolment In other States it is nowhere near it. If the diop-outs in Maharashtra is 74 per cent, what will happen in other States can very well be imagined. That means, the children go there for a year or two and thereafter because of their economic circumstances, their parents are not interested in asking the children to continue studies.* And they go back to their parents and try to help their father or mother with a little work that they can do and earn a little money$_v$ so that fhey' can eke out some living or they go and beg. Here is the crux of the matter and you will have to insist on all States to see to it that the percentage of drop-outs is reduced during the next five years.

Then I go to the opportunities that the educated amongst Harijans and Girijans are getting so far as our public sector under-takings or private sector undertakings or oiher organisations are concerned.

Sir, the figures here also are very revealing. I would ask Mr. Om Mehta, through you, Sir, to go to page 104 the figures on which will tell us that in the public sector undertakings, as on 1-1-71, you have only 0.76 per cent o^these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people in Clacs I; And, in Class II, it is 1.57 percent, in Class III—5.92 per cent and in Class IV—17.28 per cent; This was in 197 i. Naturally, therefore, we expect that when we come to the year 1972 the percentage will go up. But you will find that the percentage has not gone up, but it has actually gone down and is going down. When we come to 1972, the figures we like this:

In Clas6 I, instead of 0.76 per cent it is 0.18 per cent. There is a sharp drop and everywhere you will find that except in Class IV there is no increase at all and even in Class IV the increase is only nominal. Why? Because in Class I, Class 11 and Class 111 the employment opportunities are going up and the number of people employed is going up. But those employed or recruited from the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is coastantly going down. This is the position. And, Sir, this is the position not onty in the public sector undertakings, but also in institutions like the Oil India Ltd. and the nationalised banks. Sir, the nationalised banks and the State Bank of India have only accepted this principle that more opportunities should be given to the Scheduled Castes and Schednled Tribes. But, in practice, they are not getting any chance at all except in Class IV. Why? Because the whole caste structure is there and it is not only a question of caste, structure, but is also a question of class structure and everywhere attempts are made to elbow out the other people under one pretext or the other. What is happening io the defence forces? Sir, Mr. Jagjivan Ram was heading the Defence Ministry and he was heading the defence forces when he was the Minister there. What is happening there. I would like Mr. Om Mehta to enquire as to how many officers are there in the defence forces ,t belonging to the Scheduled Castes and Scheduled" Tribes. I do not think that he will come across anv. There may be a few who can be counted on your fingers. Why it is so ? Now, there is the Mahar Regiment. Are there any Mahar officers? No. The whole state , of affairs has come to this that even in the Mahar Regiment there are very few Maharas and it is only a name. All sorts of people are there in the Mahar Regiment.- Only the name of the Regiment is Mahar. That is all. Why is it happening? Because the tendency is to shut out

the scheduled caste people. If you bring in the Mahars, the Marathas will not be there and if you bring in these people there, the Sikhs and Rajputs will not be there because the rest of the people think that it is below their dignity to associate themselves with the Mahars. Now, in this situation, it is very difficult to see how you can give them employment even in the armed forces though they have distinguished themselves very well. Sir, in the Indo-Pakistan war in Kashmir and in other places, the Mahars have shown themselves as exceptionally valorous people, as very good fighters. In spite of this, Sir, you will find that the scope of recruitment to the army from amongst these people is narrowing and there is no scope at all as far as the officer cadre is concerned and I do not know whether any of them would become a General at all. I do not think that it is posible in our generation. Inst now, Sir, *my* friend was quoting Mahatma Gandhi as saying that India would have a real swaraj when a girl from the Harijan community would become the President. I do not know when this would happen or whether this would happen at all. Perhaps not in our lifetime. But I would be satisfied with much less and that is why I tun asking you that in your public sector undertakings, in your banks, in your nationalised banks, in your insurance organisation, why it is not possible for you to see to it ttwt at least the reserved posts go to the peoole for whom they having been reserved.

4 P.M.

The cooperative sector is coming up. My friend, Mr. Kulkarni, always speaks about it very eloquently. This cooperative sector has become almost; sectoral, caste Indian whether it is in Maharashtra or in Andhra or in Karnataka or anywhere else. How many job opportunities are they offering to the Harijans there? Why should it happen ? It is happening because of our caste structure, and, therefore, I am entirely in agreement with my friend that we must come to this conclusion that we shall do away with caste. The Congress Party should pledge itself, my party should pledge itself and the other parties too to this that whatever differences may be there is other fields, so far as re-generation and re-organisation of Indian society is concerned, we

[Shri N. G. Goray] shall have to agree on this point that theic will be no caste. Unless that is done I do nol see how this particular problem can be solved.

Lastly, Sir, the only point that 1 wanted to make is about the status of the Commis sioner. Sir, the Committee has pointed Oirt here that we have deprived him of his eyes and hands. We have taken away all the zonal offices from him. How does ha function? Sir, he has to run everywhere to collect information. The State Govern ments are not very cooperative. How does he discharge his duties which under flic Constitution he is enjoined to do? And here I would very emphatically re commend that the Commissioner must he given all the necessary help. His offi ce must be upgraded, he must be given all the help that is possible for you to give hirn. Finally, I would like to say that the task is so big that a Minister in charge of it partially will not be sufficient. Sir, when you want a separate Minister for Oil, a separate Minister for Steel, a separate Mi nister for Education a separate Minister for some other thing, do you mean to say th;;t this 22 per cent of your population, suffei- ing from discrimination, does not deserve a separate Ministry? Is it such a light thing that a Minister like Shri Om Mehta can devote his partial attention to that and solve the problems? It is not possible. It is a major question in India of so cial construction. It is a major question of social engineerini; and if it is a major question like that of irrigation or power or fuel, then I say that this also deserves a separate Ministry which will give full attention to this and it will see to it that throughout India <i uniform policy is followed.

That is all that I wanted to say.

श्री एन० पी० चौधरी (मध्य प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आज हम हजारों वर्षों से शोषित और पीड़ित हरिजन आदिवासी समाज के विषय में जो रिपोर्ट आयुक्त महोदय ने पेश की है उस पर विचार करने जा रहे हैं। आजादी के पूर्व हमारे देश के नेताओं का यह एक सपना था कि आजादी के बाद इस पीड़ित समाज का जो दर्जा है हम उसे निश्चित् रूप से उठाएंगे और उन्हें हम इतना ऊंचा उठा देंगे कि किसी प्रकार की कोई असमानता दूसरे समाजों में और इस समाज में नही रह जाएगी। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान में विशेष प्रावधान किये गए थे हरिजनों और आदिवासियों के लिये और उसी प्रावधान के अन्तर्गत हरिजन और आदिवासियों की दशा के ऊपर विचार करने के लिये, अपने सुझाव देने के लिये, एक महत्वपूर्ण पद कमिश्नर का भी बनाया गया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि अनेक रिपोर्टें इस आयुक्त ने सदन के समक्ष प्रस्तुत कीं, अनेक सिफारिशें उसकी इस सदन के सामने आई किन्तु उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया, उन सिफारिशों का बराबर क्रियान्वयन नहीं हो पाया और उसका परिणाम यह रहा कि वे सिफारिशें केवल कागजों पर ही सीमित रह गईं और हरिजन और आदिवासियों की स्थिति में वह सुधार नहीं हो पाया जो कि यथार्थ में आजादी के 22 वर्षों में होने चाहिये थे। मैं विस्तार से उन बातों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि यह एक बहुत लम्बी रिपोर्ट है, उसमें यह काफी विस्तार पूर्वक डिसकस किया गया है।

[Mr. Deputy Chairman in the Chair]

यदि मैं विस्तार से उसको डिसकस करूंगा तो शायद उसमें कई घंटे लग जाएंगे। इसलिये मैं संक्षेप में उन समस्याओं पर विचार व्यक्त करूंगा और अपने सुझाव इस विषय पर आपके सामने और सदन के सामने रखूंगा। मुझे यह कहते दुख हो रहा है कि उन हरिजनों और आदिवासियों की रोटी और मकान की जो समस्या थी आज भी वह उतनी अच्छी तरह हल नहीं हो पाई। लाखों की संख्या में लोग उसी निस्सहाय स्थिति में हैं। रोजगार नहीं मिलते, रहने के लिये मकान नहीं है, खाने के लिये उन को भोजन नहीं मिल रहा है। अत्याचार, अन्याय और उनके अधिकारों के बारे में हमारे कमिश्नर महोदय ने विस्तारपूर्वक बहुत से उदाहरण दिये हैं और हमारे सदस्यों ने उनके ऊपर अपने-अपने विचार व्यक्त किये हैं। मुझे यह बात समझ में नहीं आती है कि हमारी आजादी के 27 वर्ष बीत जाने के बाद भी, हमारे कानून में उनके सम्बन्ध में प्रावधान हो जाने के बावजूद भी, आज भी इन लोगों के ऊपर अत्याचार, अन्याय, लूटापीटी

आगजनी की घटनाएं दिन प्रति दिन होती ही रहती हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जब कि समाचारपत्रों में इस बारे में कोई न कोई रिपोर्ट अवश्य पढ़ने को न मिलती हो। इस तरह के मामले इस सदन में अनेकों रूपों में उठाए जाते हैं और शासन की ओर से हमें आश्वासन भी दिये जाते हैं कि इस सम्बन्ध में जांच की जाएगी। लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस तरह के अत्याचार, अन्याय, लूटपाट और बलात्कार की घटनाओं में कमी नहीं आई है। इसलिये मैं शासन से निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में ठोस कदम उठाएं जिससे कि इन गरीबों के ऊपर जो अत्याचार और अन्याय किया जाता है वह बन्द हो जाये।

इसी तरह से जो छुआछूत की बात है, वह आप जानते हैं कि यह रोग व्यापक रूप से गांवों में फैला हुआ है। आज हालत यह है कि गांवों में हरिजन और आदिवासियों के लिये पीने के पानी के कुएं नहीं है जहां से वे पानी भर सकें। जहां पर उनके लिये अलग कुएं बने हुए हैं वे उनके घरों से बहुत दूर स्थानों पर हैं। यदि हम इस छुआछूत की बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो हमें इस तरह का कानून बनाना होगा कि हरिजन और आदिवासी लोग भी जहां पर सब लोग कुएं से पानी भरते हैं उन्हें भी उस कुएं से पानी भरने की इजाजत हो सके।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि मैले उठाने के सम्बन्ध में कई रिपोर्टें आई हैं और उसके सम्बन्ध में कितनी बातें यहां पर कही गई हैं तथा कितने आश्वासन इसके सम्बन्ध में दिये गए हैं, लेकिन दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैला सिर पर उठाने की प्रथा आज भी हमारे देश में मौजूद है। वह सुख का दिन कब आएगा और यह हमारे देश में जो यह कोढ़ हमारे देश में फैल गया है, वह कब दूर होगा ? यह एक अमानवीय कार्य है और आर्थिक कठिनाइयों के कारण हमारे हरिजन भाइयों को यह करना पड़ता है।

इस तरह से भूमि का मामला है और इस बारे में हमें आश्वासन दिया गया है कि हरिजन, आदिवासियों तथा जो भूमिहीन हैं, उनको सरकार की ओर से भूमि दी जायेगी। लेकिन देखने में यह आता है कि गांव में जो अच्छी भूमि होती है, वह हमारे स्वर्ण भाइयों को मिल जाती है जो ऊंचे वर्ग के होते हैं और जो हरिजन तथा आदिवासी लोग होते हैं वे अच्छे जमीन से वंचित रह जाते हैं। जहां तक मैंने इस बात का अध्ययन किया है, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अब हरिजन और आदिवासियों का कोई हिमायती इस देश में नहीं है और वे आज निःसहाय स्थिति में हैं। इस पार्लियामेंट में अनेक आश्वासन दिये जाते हैं, लेकिन बात यह देखी जाती है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती ही रहती है और कोई भी उसका समाधान नहीं होता है। तो मैं इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से इस बात की अपील करना चाहता हूं कि इस विभाग को या तो प्राइम मिनिस्टर के अन्तर्गत रख दिया जाय या फिर इस विभाग को पिछड़े वर्ग, हरिजन और आदिवासी के नेता बाबू जगजीवन राम को सौंप दिया जाए, जिनके ऊपर हम नाज कर सकते हैं तथा जिनके ऊपर हम गौरव कर सकते हैं। उनके अन्तर्गत यह डिपार्टमेंट दे दिया जाना चाहिये ताकि हम कुछ राहत की सांस ले सकें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक इस प्रकार के उदाहरण आए हैं जब कि प्राइम मिनिस्टर और श्री जगजीवन राम जी के माध्यम से इन लोगों को न्याय मिल सका और उन्हें कुछ राहत मिल सकी है। कमिश्नर साहब के कार्यालय में स्टाफ की इतनी कमी है, साधनों की इतनी कमी है कि वे काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत कठिनाई के साथ उन्होंने यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। जितनी उनको जरूरत है उतना स्टाफ दिया जाये, उतने साधन दिये जाएं तो वे और शक्ति तथा और लगन के साथ अपना काम कर सकेंगे और इस वर्ग का हित कर सकेंगे।

यह कैसी विडम्बना है कि हमारे आयुक्त महोदय राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार के अनेक विभागों से काफी जानकारी मांगते हैं, काफी पत्र लिखते हैं, लेकिन महीनों तक उनको जानकारी नहीं मिलती। वे रिमाइन्डर पर रिमाइन्डर दिये चले जाते हैं। उसका भी कोई परिणाम नहीं निकलता। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि वे इसके बारे में कोई व्यवस्था करें। जब आयुक्त महोदय किसी डिपार्टमेंट को या किसी स्टेट गवर्नमेंट को पत्र लिखें तो जो जानकारी वे मांगते हैं वह अविलम्ब प्राप्त हो जानी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इन रिपोर्टों के बारे में हमको पूर्व में बहुत आश्वासन दिये गए थे, लेकिन हम नहीं जानते कि उन आश्वासनों में से कितने पूरे हुए हैं, कितने अधूरे

**[श्री एन० पी० चौधरी]**

रह गए हैं और वे कब पूरे होंगे। यदि हमारे मंत्री महोदय इस बात पर ध्यान दें कि पिछले आश्वासनों के बारे में सदन को सूचित करें कि कब तक ये आश्वासन पूरे होंगे और इन सिफारिशों को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा, तो मैं सोचता हूं कि हम लोग अपनी स्थिति को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और अपनी बातों को यहां पर उठा सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना की स्थिति है कि जो लोग देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सुरक्षा के लिये सीने पर गोली खाते हैं, उनको स्वतः अपने देश में सुरक्षा नहीं है। दिन-रात हम देखते हैं कि देश के कोने-कोने में उनके ऊपर अत्याचार होता है। खेत में दिन रात काम करके वे अपना खून-पसीना बहाते हैं, उत्पादन करते हैं, परन्तु उन्हें अपने लिये खाने के लिये अनाज नहीं मिलता। इस तरह वे परेशानियों में अपने दिन काटते रहते हैं। दूसरों के रहने के लिये वे मकान बनाते हैं, बड़े-बड़े महल खड़े करते हैं, अपने लिये उन्हें झोंपड़ा भी नहीं मिलता।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। दूसरों की भलाई के लिये वे गन्दगी दूर करते हैं, मैला ढोते हैं, शहर की और मकानों की सफाई करते हैं, परन्तु उनको रहने के लिये शहर में जो सबसे गन्दा स्थान होता है वह दिया जाता है। इस ओर कई बार ध्यान आकर्षित किया गया है, परन्तु मुझे दुख होता है कि इन सब बातों पर कोई कार्यवाही नहीं होती। परिणाम यह होता है कि दिन प्रति दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं इस सम्बन्ध में एक शेर अर्ज करना चाहूंगा :—

पड़ा जब वक्त तो खूं हमने दिया
और बहार आई तो कहते हैं कि तेरा कुछ काम नहीं।

जब देश की सुरक्षा की बात हुई, खेती की बात हुई, भवन-निर्माण की बात हुई तो खून-पसीना इन लोगों ने बहाया, लेकिन जब इन लोगों की सुरक्षा की बात आई तो कोई सुनने वाला नहीं, कोई रखवाला नहीं। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इन बातों पर हम लोगों को कुछ ठोस आश्वासन दें जिससे हम गांवों और शहरों में जाकर इन लोगों तक आपका सन्देश पहुंचा कर उनके दिल में विश्वास पैदा कर सकें।

मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इन लोगों के ऊपर अत्याचार और अन्याय की अनेक घटनाएं होती हैं परन्तु दोषी लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही नहीं होती। परिणाम यह होता है कि लोगों का दिल बढ़ता जाता है। अभी हाल की बात है कि समाजद्रोही लोगों के ऊपर, जिन्हें स्मगलर्स का नाम दिया जाता है, कड़ी कार्यवाही करने के लिये देश में मीसा का उपयोग हुआ है। मीसा का उपयोग होने से स्मगलर्स में एक प्रकार हड़कम्प मच गया है और स्मगलिंग का धन्धा बन्द होने जा रहा है। मैं यहां मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि हमारे इस देश में हरिजनों और आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, उनके अधिकारों का हनन करते हैं, उनको लूटते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं या उनके मकानों में आगजनी करते हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध भी मीसा का ही उपयोग होना चाहिये। यदि मीसा का उपयोग उनके विरुद्ध होगा तो मैं कहता हूं कि लोगों के दिलों में डर पैदा होगा, भय पैदा होगा और फिर इस तरह से जो हमें रोज समाचारपत्रों में घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं वे घटनाएं कम होंगी।

एक बात आपसे और कहना चाहता हूं कि पंचवर्षीय योजनाओं के नाम पर हमारे देश में अरबों रुपये खर्च किये जाते हैं। परन्तु हमारे इस देश में 25 परसेंट हरिजन और आदिवासियों की संख्या है, आप देखिये कि उन पंचवर्षीय योजनाओं में कितने प्रतिशत पैसा हरिजनों और आदिवासियों के उत्थान के लिये खर्च किया जाता है। यदि आंकड़े इकट्ठे किये जायेंगे तो मेरा अनुमान है कि 25 परसेंट हरिजनों और आदिवासियों के लिए, जो हमारी आबादी का एक बड़ा भारी भाग है, जो एक चौथाई भाग है, उस पर मुश्किल से 1 परसेंट रुपया खर्च होता है। यह मेरी समझ में नहीं आता कि सबसे अधिक पीड़ित, समाज में सबसे अधिक गिरा हुआ, सबसे अधिक शोषित भाग जिसके ऊपर अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहिये उस पर कम से कम पैसा खर्च कर रहे हैं। जब पंचवर्षीय योजनायें बनती हैं तो हमारे इस समाज के उत्थान के लिये उनकी आबादी के अनुपात में ही उनके ऊपर खर्च किया जाना चाहिये जिससे कि वह प्रगति कर सकें। आर्थिक विकास की अनेक योजनायें हमारे देश में लागू हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। बहुत सी फाइनेंशल

इंस्टीट्यूशन्स बनीं। एल० आई० सी० और फाइनेंशल कारपोरेशन बनी परन्तु आप देखिए कि आखिर इनका लाभ किसको मिला। इन सारी स्कीमों का लाभ हमारे देश के बड़े-बड़े लोगों को, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को मिला है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि हमारे हरिजन और आदिवासी जिनको कि आज सबसे अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है, इन फाइनेंशल इंस्टीट्यूशंस और बैंकों का एक परसेंट भी रुपया नहीं मिला है। जब कोई हरिजन या आदिवासी कोई उद्योग धंधा खोलने के लिये किसी बैंक के पास जाता है या किसी आर्थिक संगठन के पास जाता है तो उसको 200, 400, 500 या एक हजार रुपया दिखाया जाता है और वह रुपया भी ऐसे दिया जाता है जैसे उसके ऊपर कोई ऐहसान किया गया हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह आजकल की मंहगाई में, इस जमाने में दो सौ, चार सौ, या एक हजार रुपये में क्या उद्योग धंधा खोल सकता है, किस तरह से अपना आर्थिक विकास कर सकता है, वह मेरी समझ में नहीं आता। तो मैं यहां पर मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि वह इस बात को भी ध्यान में रखें कि देश के नेशनलाइज्ड बैंकों के द्वारा जो भी पैसा लोगों को कर्ज के रूप में दिया जाता है, सहायता के रूप में दिया जाता है, उसमें से एक खासी रकम, एक बड़ी रकम हरिजनों और आदिवासियों को भी दी जानी चाहिये जिससे कि वह अपना आर्थिक विकास कर सकें।

इसी तरह से रेलवे, पी० डब्लू० डी० और दूसरे सरकारी विभागों में बहुत से ठेके दिये जाते हैं। हमारे रेलवे मंत्री महोदय ने यहां पर आश्वासन दिया है कि हम हरिजनों और आदिवासियों को रेलवे में केन्टीन, कैटरिंग और दूसरी बातों के ठेके देंगे। परन्तु जब अप्लीकेशन जाती है तो वह नहीं देते। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जो सरकार के बहुत से डिपार्टमेंट हैं जहां पर ठेके वगैरह दिये जाते हैं उनमें भी हरिजनों का एक प्रतिशत निश्चित होना चाहिये जिससे कि वह ठेके उनको मिल सकें और वह अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें।

उपसभापति महोदय, इसी तरह से लाइसेंस और परमिट या कोटे की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हरिजन तथा आदिवासी भाइयों को किसी प्रकार के लाइसेंस, कोटे या परमिट नहीं दिये जाते हैं तथा उनको दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है इसलिये उनको इन अधिकारों से वंचित किया जाता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि जब बड़े-बड़े उद्योगपति लाइसेंस और परमिट लेने का अधिकार रखते हैं तो क्यों नहीं सरकार ऐसी नीति बनाती जिससे कि हमारे छोटे-छोटे हरिजन और आदिवासी भाइयों को भी, जो आर्थिक स्थिति में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनको इसका लाभ मिले और वे अपना आर्थिक विकास कर सकें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे धंधे हैं जिन पर एक प्रकार से हमारे हरिजन और आदिवासी भाइयों का ही अधिकार होना चाहिये। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि उनकी खून पसीने की कमाई को दूसरे लोग ले जाते हैं और हरिजनों को उससे वंचित कर देते हैं।

मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि जो जंगल में काम होता है उसमें हमारे आदिवासी भाई ही काम करते हैं, हरिजन भाई ही काम करते हैं परन्तु उनको मुश्किल से रोटी खाने के बराबर ही मजदूरी दी जाती है और बाकी जो बचता है वह बड़े-बड़े ठेकेदार ले जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश में ऐसी नीति बनाई जानी चाहिए कि जहां पर जो काम करता है, खून-पसीना बहाता है ऐसे कामों में केवल उन्हीं को अधिकार होना चाहिये और किसी दूसरे को उसका लाभ नहीं होना चाहिये। इसी तरह से आप देखेंगे कि खाद्यान्नों में बहुत से मजदूर हरिजन और आदिवासी भाई काम करते हैं। परन्तु मजदूरी के रूप में उनको छोटी-छोटी रकम मिलती है और सारी उसकी मलाई दूसरे ठेकेदार खा जाते हैं। इस प्रकार से उनकी आर्थिक स्थिति रुक जाती है।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जब शहरों का निर्माण होता है बड़े-बड़े मकान बनाए जाते हैं तो इन बेचारों को फैंक दिया जाता है। हमारे इन गरीब भाइयों को भी गन्दी बस्ती उन्मूलन के नाम से शहर से बाहर फैंक दिया जाता है, मकान खाली कराये जाते हैं उनकी झोपड़ी तोड़ी जाती है। आप समझिए कि शहर के विकास के रूप में, शहरों की सफाई के रूप में उन गरीबों को हटा कर शहर से हटा कर एक गन्दी बस्ती में फैंका जाता है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब किसी शहर में गन्दी बस्ती उन्मूलन का प्रश्न आता है या उनके पुनःनिर्माण की बात आती है या शहर के विकास की बात आती है तो उस वक्त हरिजनों और आदिवासियों के हटाने की पहले लिस्ट बना लेनी चाहिये और जो नए

**[श्री एन० पी० चौधरी]**

मकान उस जगह पर बनते हैं, जो नये भवन बनते हैं उनमें उनको बसाया जाना चाहिये । यह नहीं होना चाहिए कि जो लोग पीढ़ियों से यहां पर रहते आये हैं गन्दी बस्ती उन्मूलन के नाम पर बाहर फैंक दें या उनके अधिकार से वंचित कर दें । (*Time bell rings*) सभापति जी, मैं पांच मिनट में समाप्त कर दूंगा ।

म्यूनिसिपलिटी में, कारपोरेशन में और डी० डी० ए० में बहुत से मकान और दुकानें बनाई जाती हैं । अगर आप लिस्ट देखें तो आप को यह पता लगेगा कि । परसेंट मकान भी इन हरिजन आदिवासियों को नहीं मिलते हैं, एक परसेंट दुकान भी उनको नहीं मिलती हैं । क्या हमारा यह अधिकार नहीं है, क्या हरिजन आदिवासियों भाइयों का यह अधिकार नहीं है कि उन दुकानों को ले सकें और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में किसी प्रकार से प्रयास कर सकें । जो दुकानें बनती हैं, मकान बनते हैं वह बड़े-बड़े लोगों को दी जाती हैं । मैं यहां पर मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि ऐसे मामलों में देखें और दुकानों और मकानों में भी उनका कोटा रिजर्व होना चाहिये जिससे कि वे अपना कारोबार संभाल सकें और अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें ।

मैं एक बात आप से कहना चाहता हूं कि देश की यह विडम्बना है कि हमारे देश में ऐसे लोग सदियों से राज करते चले आ रहे हैं जिनको हमने राजवंशी नाम दिया है जिनकी संख्या 10% है और यह 10% 90% लोगों पर इस देश में राज कर रहे हैं। इसका यह दुष्परिणाम हो रहा है कि देश की पीड़ित जनता, हरिजन आदिवासी और पिछड़े लोग जहां के तहां रह गए हैं । उनका विकास नहीं हो पा रहा है ? उनको नौकरियों में जगह नहीं मिल पाती है । सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनका पालन नहीं हो पाता । नौकरियों में उनको कोटा नहीं मिलता । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपको एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिसमें राजवंशी नौकरी न कर पाएं, उन पर आपको पाबन्दी लगानी पड़ेगी । यह उस समय तक कायम रहना चाहिये जब तक हमारे आदिवासी, हरिजन भाइयों को उनके प्रतिशत हिसाब से नौकरी नहीं मिल जाती, परमोशन पूरी नहीं मिल जाती, उनका कोटा पूरा नहीं हो जाता । मैं समझता हूं अगर आप इस तरह से कर पायेंगे तो एक बड़ा भारी उपकार हमारे ऊपर करेंगे, हमारे हरिजन भाइयों पर करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, परमोशन और नौकरियों की भर्ती के बारे में हमने देखा कि कोई न कोई बहाना बना कर हमारे हरिजन भाइयों को नौकरी का फायदा नहीं दिया जाता है, उनको परमोशन नहीं दी जाती है । मैं हरिजन कल्याण समिति का सदस्य रहा हूं । उसके कारण मैंने देश के कई भागों में भ्रमण किया है । जहां भी गया हूं मैंने साक्षी ली है । वहां से यह पता लगा है कि वहां के लोगों में एक मानसिक भ्रम है और जब तक यह भ्रम खत्म नहीं होगा तब तक हमारे इन हरिजनों, आदिवासी भाइयों को कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस को भी आपको देखना पड़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से एक बात और है । सैंट्रल गवर्नमेंट मैडिकल और इंजीनियरिंग कालेज में जो कोटा होता है और फारेन स्कालरशिप मिलता है या पब्लिक स्कूल और सैनिक स्कूल में भर्ती होती है हमारे हरिजन भाइयों का उसमें कोई हिस्सा नहीं होता है ।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर विचार करें और हम लोगों के जो अधिकार हैं उनको देने की कृपा करें जिससे कि हम लोगों को राहत की सांस मिल सके और हम लोग आपको धन्यवाद दे सकें ।

इस संबंध में लाइजन आफिसर के रूप में हर डिपार्टमेंट में एक लाइजन आफिसर काम करता है । लेकिन अगर आप इस अधिकारी की ड्यूटी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह काम केवल खाना-पूर्ति के लिये रखा गया है । ऐसी हालत में मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप सच्चे दिल से लाइजन आफिसर की नियुक्ति करना चाहते हैं तो आपको इस काम के लिये अलग से आदमी रखना होगा और अलग से इस काम के लिये नियुक्ति करनी होगी ताकि वह व्यक्ति अच्छी तरह से हरिजनों और आदिवासियों के हितों की रक्षा कर सके । अगर आप अलग से आदमी की नियुक्ति नहीं करते हैं और डिपार्टमेंट के आदमी को ही यह काम सौंपते हैं तो यह काम उसी तरह से है जिस तरह से एक अपराधी

स्वत: ही न्याय करने वाला हूं । इन शब्दों के साथ में निवेदन करता हूं कि जो भी विचार मैंने व्यक्त किये हैं उन पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करें और हम को न्याय दिलाने की कृपा करें ।

SHRI S. S. MARISWAMY (Tamil Nadu): Mr. Deputy Chairman, Sir, this question of the uplift of Scheduled Castes and Scheduled Tribes was very much in the forefront during the Second Round Table Conference.. You will remember that Mahatma Gandhi, when there was the talk of a separate electorate, undertook a fast in the Yelrawada jail. It was then promised that this Question would be given the topmost priority to be tackled in independent India. It was on this assurance that the Harijan community opted for the general electorate. You may remember that one M. C. Rajah from Madras went all the way to Yerrawada jail to persuade Mahatma Gandhi to give up his fast. Also, he was instrumental in bringing round the late Dr. Ambedkar to the view of Mahatma Gandhi but question has now become a ritual. Once a year or twice a year we take up the Report of the Commissioner and discuss tbe whole matter. This time I am glad that this is the second time Mr. Mohsin is here to hear the Members giving vent to their grievances and painting the real nic-tnre of india. My own view is that the Government of India led by the Congress party has not cared to bestow as much attention as the question deserves. They have been dillq-dallying with this issue for such a long time. They themselves have forgotten what the earlier leaders have ed Ihe community. They have lost all seriousness. For them also it has become a ritual. Mr. Mohsin is very patient and he is spending a couple of hours here listening to the speeches. I do not know what would follow, but my experience is that nothing takes place. * I have nothing personalty against Mr. Mohsin who is in-"harge of this, but things are in a sorry state of affairs. For the last 27 years you have not done anything. My friend, Mr. Rabi Ray, quoted Mahatma Gandhi, who wanted a Harijan girl to be elected the President of India. We tried our best to have one Harijan from Madras, Mr. Siva-shanmugham Pillai, to be the Vice-President during the last election when he contested, but you know very well that thf suling party voted against him. This wa* our humble attempt attempt at getting one Harijan if not as the President at least as the Vice-President of India. Anyway, most of the Members who spoke from that side-I could see, spoke with qualms saying that much had not been done. At the same time there was bravado and that is really the pity. These are national questions. We must cut across party-lines and talk about what is really needed in the present day Ii the Government is very serious and the Congress Party is also equally serious, they should have taken up ihe matter at the party-level and they should have taken an assurance from the Chief Ministers of various States. They rule all over India, except in one small State to which I belong. They should go to the root and have these reforms implemented-with all seriousne:w and in all sincerity, but they have done nothing so far. For example, one non-Coueress Ministrv is in Madras headed by Dr. Karunanidhi, I give below a few achievements of ours in this direction. 1 do not say it in a boastful manner, but in a humble spirit. I say it in this august House so that some of the Members, when they go home, can persuade their respective Chief Ministers to implement some of these things. For the last 22 years there was a raging question about the allotment of what you cad home steads or residential buildings or the Harijan community wherever they are found to be tilling the soil, they are tillers of the soil, but they were not provided with any shelter.

All the Congress Governments—I am sorry to say—have miserably failed to solve this problem. It was the DMK Government that has tried to solve it. In Tanjore which is considered to be the rice

>wl or granary of South India and which a Use a very fertile place where a *lavs* majority of the people belong to that com munity, for the firsl time they were given these homesteads; and also in Tiruchirapalli and other places, hundreds of thousands

|bhn b. S. ManswamyJ

of people have been benefited by this scheme for the first time in their Kves. Secondly, we have constituted a Corporation called tlie Harijan Housing Corporation with a mandate that this Corporation should construct ten thousand houses annually for the Harijan community, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. And this Corporation is going round the countryside and is setting up colonies with a view to constructing ten thousand houses per year. This is our target. I am quite sure that it will succeed in it; I am quite sure also that we will be fulfilling whatever commitmerts we have made. Thirdly, we have introduced a novel scheme—and I am glad|that Shri N. G. Goray has also here touched upon that. We have been shouting from the house-tops that we must see that the caste system is abolished. But how to do it? As a matter of fact there was the question asked by one of the Congress lady members of the^ Commission about the chastity of the Harijan women. Shri Goray has pointed out .'his. My blood re*ally boils over such an attitude; this is the attitude taken. The caste superiority has not disappeared. It is still there very much for all of us to see, not only here but all over India, and it is the bane of ihe society. But what hav^ we been doing ?, We have been preaching every day that the caste system must go. Forget the caste system, now it is the class system. We talk of the class -system. Mr. Mohsin is one of the invitees to a conference. In a week's time they are going to meet at Narora, 70 Km. from Delhi. And they have selected 70 top members of the Congress Party to chalk out their strategy for 1975. I do not believe in numerology or in astrology. But a friend of mine was telling me—add 70 and 70 and 75. It comes to 215. Two plus one plus five equal eight. *Theen, therah. aat, attarah*____ all these are bad numbers. T do not know what you are going to get out of eight. Like Cassandra I do not want to spell out that something bad is going to happen. I hope your conference is a successful one; I wish it success and I wish you bring out a good strategy. • cut would you nave tne guts to bring out a resolution that this party will be out to see that the caste system is abolished in two years' time or in five years' time or even in 10 years' time for that matter? Would you do that? Instead of talking about this or that. ... •SHRI IAGANNATH BHARDWAJ (Himachal Pradesh) : Why not all the parties? Yourself also.

SHRI S. S. MARISWAMY: If you listen t0 me, you will understand what 1 am saying. This is only the preamble; this is not a bomb. What rrly party and my Government have done is this. We have passed a Resolution in the Assembly that if anybody marries a girl of the lower caste, he will be rewarded. That is to say, if a Brahmin marries a Harijan lady or vi'cc-*vcrsa,* the couple would be presented with a gold medal. In other words, the State would honour them. After this announcement was made, my Chief Minister has gone round the State and has presented gold medals. And the movement has gained so much momentum ar.d speed. Now it has become the order of the day; it is the fashion for the youngsters to marry into the lower caste. This is what a small party, a State party, and a State Government in one of the States has done, when all over India Mhe Congress Party is in power.

*It* we can do this what effect it will have if the Central Government does it. the bigger party, the Congress party does it ? There will be a real change in the outlook of the entire country. This is what I want the Government to do. That is why I ask the men and women in the Congress that when they assemble in Narora they must think on those lines instead of thinking how to win the next election, how to manioulate the ballot boxes etc. I do not want to go much into that.

Then, Sir, we had .taken a vow to under-take the job of electrifying every Harijan colony within 1974. I am glad the job has been well done. I am glad to say tbat there is no hamlet, no village, no town, no colony in Tamil Nadu inhabited by Harijans even in inaccessible places where

electricity has not reached. And it was done, for your information, in October itself.

Thirdly, we have reserved for them 49 per cent. seats both in the academic and professional colleges. Even Government jobs to the tune of 49 per cent. have been reserved for backward classes and Scheduled Castes and Tribes. No other State in India could do it.

Finally, Sir, we have instituted a number of co-operative societies for advancing money to Harijan youngesters who are enterprising, who are industrious, to start business. For running enterprises, from opening petty shops to running road transport we have advanced money to Harijans. As a result a number of societies have come up all over the 14 districts of Tamil Nadu mainly for the Harijans.

Sir, as you know we have a small Cabinet when compared to the States of Uttar Pradesh, Rajasthan and Madhya Pradesh. It comprises of only 15 members. But we have got two Cabinet Ministers belonging to the Harijan community. Never before such a radical step has been taken anywhere in India. It is for the first time that the D.M.K. Government has given two seats to the Harijan community.

Then, Sir, you know very much about Madras affairs and it would be carrying coal to New Castle if I tell you something about the affairs in Tamil Nadu. Sir, for the first time in the history of the Madras High Court, the High Court Bench is adorned by a Harijan member. Though it is the President who is pleased to appoint a Judge, it is the State Government which has to recommend the name for his approval.

Sir, the South is famous for temples. In each and every temple there is a Trust Board. During the previous regimes these Trust Boards were nominated on a partisan basis. Then only people belonging to the ruling party were having a predominant position. They all belonged to the upper classes. People from top class were finding place on the Board. But after the advent of the D.M.K. Government we have made it a point to appoint at least one member belonging to the backward community on the Trust Board attached to a temple. Meenakshi temple, next in fame to the Rameswaram temple, supposed to be very famous and sacred and important, where people from all over India, from Rajasthan and other places take pilgrimage, is having a Harijan as its Trustee. When they appointed a Harijan as its Trustee there was great resistance. There was a movement. Even now that movement is not dead. There is resistance by people who have connections and upper hand here. They have got their friends in Delhi. They are still trying to manipulate here. These people are hundred per cent anti-Harijan. Here they catch hold of some useful people for this purpose They catch hold of people who have committed economic offences under Foreign Exchange (Regulation) Act and various other Acts and who unashamedly address press conferences and say that they receive black money because the black money that they receive is for good purposes. And it has come in cold print. I have been telling all my friends yesterday and the day before that I find no difference between such of those people who say openly "I take black money, but there is a difference; others take it for hoarding but I take it for spending for good purposes" and people like Haji Mastan. So far as I am concerned, I find no difference between such people and Haji Mastan, Yusuf Patel and Bakhia. They are all the same. As a matter of fact, I was in Bombay a week after the arrest of Haji Mastan. I met a cross-section of the people. I had gone there for a Joint Select Committee meeting. I met a number of people, people associated with cinema, people associated with religious bodies, people who are working journalists and people who are in business. I was really surprised and I took up cudgels against them when they started praising these fellows. They said they are great philanthropists, they have donated money to mosques, churches, temples and various other charitable institutions.

[Shri S. S. Marisw*iy]

I stud "You are eulogising these people. It is not proper for right men to do that". That should be the attitude of the Government also. But we find such people associating and rubbing shoulders with the powers that be here. I am really ashamed. If there is no encouragement given to them, how would they dare to come out in cold print with a statement like this? I will read another statement.

> "It will be no exaggeration to say that after Nehru, Indira Gandbi is the most successful political leader in India."

Can you guess who is he ? And the man goes to the extent of saying that he has been associated in active politics from 1942 when the Quit India Movement was started by Mahatma Gandhi, and he was a revolutionary and yet a true follower of Mahatma Gandhi. Sir, our memory is very short.

SHRI D. D. PURI (Haryana): Who js that gentleman ?

SHRI S. S. MARISWAMV-. Since my good friend, Mr. Puri, has asked me, I cannot withhold the information. He is Mr. M. G. Ramachandran, swashbuckler and celluloid hero of Madras. . .

SHRI N. P. CHAUDHAR1: For years he was your friend.

\ SHRl S. S. MARISW AMY: We used him as a show-boy and now you are using him. *{Interruption).* He was my show boy before and now he is your show-boy. Is there no difference between you and me? After all, I am a chhota aadmi" and you are a "bada aadmi". You rule the whole of India. You have a long history. And your leader is one of the world famous leaders to be associated with this man. *(Interruptions). Ihe* 1942 movement is still green in our memory When we think of j 1942, we think of heroic persons—Jayaprakash, Aruna Asaf Ali, Lohia, Achut Pat wardhan and a number of people from Bengal, from Andhra and from Madras. It is such giants who go in a train before our eyes. Whenever we heard the names cf JP Achut and Aruna Asaf Ali, we were very much touched. As a matter of fact, one wintry evening, I took my life in my hand to go to Madras Central Station to receive Aruna Asaf Ali when she was underground and came in the guise of a Muslim, in a burqa. I took my life in my hand and went to the station. With great difficulty, 1 brought out that lady, took her in a "jutka" and lodged her in a place. The very same night the Policemen started going round the house. Those were the days when it was as easy to kill a Congressman or a nationalist as to kill a mad dog on the road. Sir** were the days and now this great hero says that he took part in 1942 movement. You were in Madras. You were a student in Pachaiyappa's College. Had you heard of this pigmy who now says that he took part in 1942 movement ? Look at the lie he is uttering. These are days when people can utter -lies and there are lots of people who believe them. It is a pitiable thing. Look at the audacity and tetmerity of this man who says that "it is hard tc believe that this symbol of massive populanly can with just one snap of his fingers bring the whole of Tamil Nadu to his doors". Thank God, not to his shoes, but only to his doors. This is from a pamphlet prepared by himself. Does he think that people of Madras are dogs or puppies to be called by snap-? All these things would not have been there, but for the encouragement given to him to do mischief in Madras. Who are the people who support hirn ? They are the people who are against all the reforms done in Madras and they are the people with vested interests who want to take the country back to 200 years. These are the reactionary elements not only in Madras, but all over India, supporting him and particularly in Madras with a view Ic topple the progressive Government of Madras which stand by their own achievements. I can place this on the Table and I challenge that if I have exaggerated even an iota, I am ready to withdraw whatever I have said. If this man, as he says, has taken part in 1942 movement, if he had even

gone to a Police station under tbe Nuisance Act in 1942, I am prepared to retire fram politics.

SHRl B. RACHAIAH tkarnaraka): Mr. Deputy Chairman, 1 rise to make a few observations on the reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1971-72 and 1972-73. Many members on this side as well as from the other side have taken lot of interest ia going through these reports. They have not only gone through these reports, but have expressed their sympathies and spoken in unequivocal terms tb;it *more* efforts have to be made *to* make these people to come up to the level of other people in the country. I thank them for the sympathy they have expressed for these people.

Coming to the report, the Commissioner has made a very general ooscrvation that there have been let of omissions and commissions and deficiencies and inadequacies in the implementation of the various programmes and policies laid down by the Centre and ihe State Governments. He has quoted the Prime Minister's clarion call that_we should not neglect the weaker sections and we have to take them along with us in ths path of progress and these disparities should not be continued for ever. He has also in a distressing voice said that there has been a lot of difference in what we preach and what we practice. The utterances and statements of national leaders have fallen on deaf ears of the leaders at various levels and ths implementing authority. It is not correct to say that nothing has been done. The country has progressed'in several fields.

But these Scheduled Caste and Scheduled Tribe people have not been benefited out of these national activities to the required or desired 'extent and it is because of the social barricades that have been built between the different communities. *I* do agree that the caste barrier is not confined only to the Scheduled Castes and the other castes. It is there even among the caste Hindus and also among the Scheduled castes and it is only a question of degree. But between the caste Hindus and the Scheduled Castes th?rc is a vast difference and even today, a3 some honourable Members pointed out, they are unapproachable and untouchable and they remain as they were previously despite the Government's policies and programme*. But, Sir, I must say on this occasion that in the field of education and in the field of services, certain amount of progress has been achieved. If I start mentioning all the points mentioned in tbe Commissioner's Report, I will not find time because he has made nearly 278 recommendations. Some of these recommendations have been partially implemented and some of them are yet to be complied with.

Coming to the organisation. Sir, as has been pointed out by many Members here, the Commissioner has been appointed under article 338 of the Constitution which imposes an obligatory duty on the part of the Commissioner to take such action as is necessary to investigate and to collect all the necessary d:i'a and to report to the President who in turn causes the Report to be placed before both the Houses of Parliament. Sir, it is surprising to note that when seventeen offices, regional offices which were established earlier, they were all of a sudden abolished just to provide regional offices to the Directorate-General of Social Welfare. I have *not* objection to the DG, Sociui Weifare getting such regional offices. But this should not be done at the cost of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. He has to depend on borrowed information. Sir, in most of the appendices to the Report, you will,come across the words "NA" meaning "Not available". Most of the information which has been called for by the State Governments is not made available and it is because he has no •source of his own to collect all the neeessary data. In spite of this difficulty, he has been able to produce a good Report, a ;eport which^ will indicate the atrocities and the crimes that are being committed day in and day out these days. These are only a few

[Shri B. Rachaiah.]

examples of the types of crimes that are being committed en these unfortunate people. Sir, these are not the only cases of atrocities and crimes committed on these people but there are many more unnoticed.

Sir, the other day, on 11-11-74, the "Statesman" mentioned that during the last six months nearly 2,778 Crimea have been committed and it says how even after 27 years of our independence crimes and atrocities are being committed by the people without any hum&n consideration. I need not go into the details of these things. They ate there and they will continue to be there. But, Sir, fwould like to take this opportunity to make a few suggestions for the consideration of the Minister concerned.

Education is really helping the Scheduled Caste and the Incheduled Tribe people in every respect. But, unfortunately, admissions to the middle schools and the high schools are becoming less and less in number because of the poverty of the parents of the boys and girls.

The Commissioner has mentioned that we shall have to see that the number of hostels will have to be increased and a number of scholarships at the middle school and high school level will have to be given. I know, Sir, that Education is a State subject. In order to help the State Governments, the Central Government has come forward to give post-matric scholarship. So far as my State is concerned, we have exempted the Scheduled Caste and Scheduled Tribes students fiom payment of . tuition fee from the primary school to post-graduate level ;*no fee is levied except sports fee and library fee. Now, after introduction of these post-matric scholarships, the State Governments are being benefited in this way. That is being reimbursed by the Centre. These have to be separated. There should be freeships separately and the maintenance grants separately. The recent increase of these scholarships has been only fcr about 10 per cent or 20 per cent to day scholars. But they have done injustice by restricting it only to two candidates belonging to a parent or guardian. The Scheduled Castes candidates who could not afford to join the college have joined service and continue their graduation. They have been denied this opportunity. It is the Government officials who have come to Delhi and other important cities. They are joining evening colleges and they have become graduates, even double graduates, and they have fared well even in the IAS or IPS examinations. Therefore, when we fix higher qualifications for services, then it is all the more necessary that these discriminations are removed, and everybody, irrespective of the course, is given this freeship and- scholarship up to the postgraduate classes. This is the only way by which you cai: improve the conditions of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. For all the maladies of this class of people it is only education that is a sovereign remedy, as far as I can see. These scholarships should not he restricted only for two children; but rlso should be given to all children and the officials also should be given. The restriction that only those are entitled to get scholarship whose parents' income is less than Rs. 750, should also go, because untouchability has been there even prior to independence and even after that it continues to be there. I do not think that in this land of ours we will' be able to remove untouchability. Even under the Constitution, the caste bas not been removed. It is only in the preamble of our Constitution that we have accepted Justice, Liberty, Equality and Fraternity. How far these four assurances, so solemnly given, have been implemented, is a question which remains till today Therefore, I api not going to touch the sentiments >of caste Hindus. I would only appeal to the Minister-in-ch.irge to try to give them all necessary help *o become educated so that they wiH know their rigWs and privileges and they will no longer feel that they are inferior to any section of the society.

The second thing is that in giving scholarships also certain restrictions have been put in the post-graduate courses also.

5 P.M.

If he wants to change to another course while continuing a particular course, it is also denied to hirn. It should not be done. Even the foreign scholarships which were used to be given earlier have been stopped. Therefore, there is a lot to be done in the field of education alone. The hostels for girls have to be built. Othrwise, we cannot have any progress. In the remote corners where the hill tribes are there, the Ashram hostel schools are the only solace for these people. They are able to study in these school's and able to become good citizens of this country. Now I come to service safeguards.

No doubt, the Government have issued orders for reservation of vacancies for direct recruitment. Recently, they have also given orders for reservation where the direct recruitment to Class III or Class II or junior Clases I posts does not exceed 50 per cent. The Government has also been pleased to issue an order that even in private agencies, and autonomous bodies which are getting Government aid, there should be'certain reservations according to the population of this class of people. If these orders are properly implemented, it will go a long way in ameliorating the condition of these people. Implementation is the most important part of il. Except the Union Public Service Commission at the Centre and Public Service Commissions at the State level, there is no Scheduled Castes representative or Member in the recruitment committees at the State level. There are several recruitment committees at the State level which screen the applicants for appointment to various posts in Class III and Class II. Therefore, I insist upon the Government to issue necessary directions that in all these recruiting bodies, banks or corporations, or autonomous bodies there should be a Scheduled Castes Member to safeguard the interests of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

There should he a cell in every depart-" ment to look after the privileges and the rights of these people and to see whether the rules, guarantees and the directives are being implemented.

Coming to the Commissioners report itself, he has suggested certain modifications in the Planning Cell in the Planning Commission. In the Planning Cell, there is only one Personnel Officer who is looking into the various welfare schemes for the Scheduled Castes. Nearly Rs. 235 crores have been earmarked for the welfare of the Scheduled Caslcs and Scheduled Tribes in the Fifth Fiv; Year Plan and about 500 crores of rupees have been set apart for the tribal development. This is a fairly big sum. Therefore, there should be a separate cell to look into these matters. I would urge, through Mr. Om Mehta, to the Prime Minister that a Scheduled Castes Member should He appointed in the Planning Commission. Are we not able to find a capable person who is well-versed with the difficulties of the Scheduled Castes people to be a Member of the Planning Commission. When we are represented in the Parliament or in the State Legislatures can we nokfind a suitable person for this post?

SHRI RABI RAY: I think that the Prime Minister thinks that Mr. Haksar who is going to be the Deputy Chairman, is a Harijan.

SHRI B. RACHAIAH: Even the Commissioner has recommended that there should be separate units in the Home Ministry for the welfare of ihe Scheduled Castes, Scheduled Tribes, de-notified and semi de-notified tribes. He has pointed out that there is no reservation for the Vidhan Parishads at the State level and the Council of States at Ihe Centi e level. He has made an appeal to all the parties concerned to select candidates from amongst these classes of people to contest the unreserved seats. I have been watching for the last 20 or 25 years that this has$_t$ remained as merely a hope. Therefore, I would request the Minister concerned to bring amendments to the relevant provisions of the Article in the Constitution to make reservation for this class of people in proportion to the members in the lower House to All the posts in the Vidhan Parishads and in the Rajya Sabha.

*(Time bell rings)*

[Shri R. Rachaiah]

So far as distribution of land is concerned, Mr. Malaviya was suggesting that the land problem of this class of people has to be solved. I know, Sir, how the land which is unsuitable foi cultivation is being given to these people at the village level in many parts of the country. I have seen it. Therefore, certain rules have to be framed whenever the land is proposed to be allotted. In the land distribution committee, the Scheduled Caste people should find a place. Sir, in cities and towns, we find that the housing corporations and the trust boards are building houses. And the Government quarters are also there. Even there, if certain icservations are made for giving shelter to the Scheduled Castes and Tribes people, to that extent, they do not feel the untouchability. It is not the elder generation, beionging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes , the intensity of this caste feeling. It is the educated people belonging to these communities that arc feeiing the intensity of the caste feeling that is generated out of these caste barriers. They are feeling it. Therefore, it is necessary that such a discrimination is not made in government offices. I find that in most of the offices, they are not prepared to have them even as Class IV servants just because they have to work in their houses and, therefore, their wives and their f?mi!y members object to it. Even today. This is prevailing. If such is the case, how can we expect justice from the lower level 7 Therefore, I do not blame the innocent masses of this country for observing untouchability but I blame the educated section of the country for continuing this hatredness towards this class. They must think now and revise their opinion to give the proper place to these people. So, proper education and service safeguards these things can alone make us feel that we are also taking a share in the develop-mental activities. Sir, after 1970, certain real measures have been taken. T once again say that (hose measures have to be implemented in earnestness. If any officer or any authority violates that, action has to be taken and they should be dealt with properly. Thank you, Sir.

## MESSAGE FROM THE LOK SABHA

### The Constitution (Thirty-second Amendment) Bill, 1973

SECRETARY-GENERAL. Sir, I have to report to th? House the following message received Irom the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:

"I am directed to inform Rajya Sabha that Lok Sabha, at its sitting held on Monday, the 18th November, 1974, adopted the following motion in regard to the Constitution (Thirty-second Amendment) Bill, 1973.—

'That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do appoint two members of Rajya Sabha to the loint Committee on the Bill further to amend the Constitution of India in the vacancies caused by the resignations of Sarvashri Ram Niwas Mirdha and Umashankar Dikshit and do communicate to this House the names of the members so appointed by Rajy^i Sabha to the loint Committee.'

2. 1 am to request that tbe concurrence of Rajya Sabha in the said motion, and also the names of the members of Rajya Sabha so appointed to the Joint Committee, may be communicated to this House."

| MR. DEPUTY CHAIRMAN : The House stands adjourned till 11.00 A.M. tommorrow.

The ' House then adjourned at ten minutes past five of the clock / till eleven of the clock on Wednesday; the 2')th November, 1974.

MGIPRRNli— Sec. VIII —77 RSS/74—30-1-75— 595